RNI NO. CHHHIN/17604 TC

लाईफ वर्सिटी

मासिक

जिंदगी संवारने को तो
जिंदगी पड़ी है,
वो लम्हा संवार लो
जहां जिंदगी खड़ी है

वर्ष : 1 | अंक : 07 | माह : दिसम्बर 2023 | पृष्ठ : 8 | संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, 8817194979 | मूल्य : 5 रू.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव ही क्यों

धर्मकर्म का यही माहौल आदिवासियों को रास आता रहे, इस की जिम्मेदारी अब विष्णुदेव साय को दी गई है. विष्णुदेव साय भी उत्साह में हैं क्योंकि उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कई दिग्गजों को किनारे करते भाजपा आलाकमान उन्हें यह मौका देगा.

तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए लौटरी के ईनाम जैसा रहा एसे मे मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा भी लौटरी से कम नहीं रही । और इनाम मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद मिला विष्णुदेव साय को जो आदिवासी समुदाय से आते हैं.

4 बार लोकसभा सदस्य रहे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री 59 वर्षीय विष्णुदेव साय की प्रमुख खूबी यह है कि वे प्रतिबद्ध भाजपाई और जनसंघ की पृष्ठभूमि वाले नेता हैं, यानी हिंदुत्व उन के खून और मिजाज दोनों में है. उन के दादा बुधनाथ साय और ताऊ नरहरी प्रसाद साय भी जनसंघ से विधायक चुने गए थे.

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भाजपा ने वीआरएस देते हुए विधानसभा अध्यक्ष बनाकर सम्मानजनक विदाई कर दी है तो अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाते हुए उन्हे एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी लगभग 33 फीसदी है जो 90 में से 30 सीटों पर सीधे प्रभाव रखती है. और जिस कुनकुरी विधान सभा सीट से विष्णु देव जीते हैं वह सरगुजा संभाग की है जहां की सभी 14 सीटें भाजपा की झोली में गिरी हैं. इतना ही नहीं, हैरतअंगेज तरीके से बस्तर की 12 में से 8 सीटें भी उसे मिली हैं. यानी, इस बार आदिवासी भाजपा पर ठीक वैसे ही मेहरबान रहा है जैसे 2018 के चुनाव में कांग्रेस पर रहा था.

जब कांग्रेस ने इस राज्य का पहला मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारी अजित जोगी को बनाया था तब उन की जाति को ले कर सवाल भी उठे थे और बवाल भी मचा था कि वे सचमुच के अदिवासी हैं भी या नहीं. अजित जोगी की जाति का मसला उन की मौत के बाद तक पहेली बना हुआ है जिस के अपने अलग सियासी माने हैं. आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भी उठी थी लेकिन भाजपा ने भी उस पर गौर नहीं किया था.

2018 में जब कांग्रेस भारी बहुमत से सत्ता में आई तो उस ने पिछड़े तबके के भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया जिनके कार्यकाल को बेहतर कहा जा रहा था. वोटर ने उन्हें क्यों नकारा, इस की वजहें अच्छे अच्छे विश्लेषकों को भी समझ नहीं आ रहा .

चूंकि सत्ता में वापसी की उम्मीद कम थी इसलिए भाजपा ने साल 2023 की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ में संतों की धार्मिक यात्राओं शुरू कराई जिसका शुरुआती असर तो नहीं दिखा था लेकिन फरवरी में विश्व हिंदू परिषद ने 700 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन किया था जिसके संयोजक थे सर्वेश्वर दास महाराज.हिंदू राष्ट्र की मांग करती 500 संतों के हुजूम वाली यह पदयात्रा एक महीने चली थी और शिवरात्रि के दिन आदिवासियों के सब से बड़े मंदिर मां दंतेश्वरी में जम कर पूजापाठ व यज्ञहवन हुए थे जिस में बड़ी तादाद में आदिवासी मौजूद थे.

इस यात्रा से तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने बौखला गए थे कि उन्होंने बड़े पैमाने पर राम वन गमन पथ विकसित करने का ऐलान कर दिया था. और यही भाजपा चाहती थी कि कांग्रेस भी साधुसंतों, पूजापाठ और यज्ञहवन की राजनीति करे जिस से आदिवासियों में हिंदुत्व की फीलिंग आ जाए.

धर्मकर्म का यही माहौल आदिवासियों को रास आता रहे, इस की जिम्मेदारी अब विष्णुदेव साय को दी गई है. विष्णुदेव साय भी उत्साह में हैं क्योंकि उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कई दिगगजों को किनारे करते भाजपा आलाकमान उन्हें यह मौका देगा.

ऐसे ही चौंकाने वाला फैसला भाजपा ने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हुए लिया था जो अब पूरी तरह से धर्म और पूजापाठ की राजनीति कर रहे हैं. हरियाणा में मनोहर सिंह खट्टर को भी इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया गया था कि वे कट्टर हिंदुत्व के हिमायती हैं. छत्तीसगढ़ मे आदिवासियों का कितना भला होगा, और भाजपा को कितना लाभ सामने है लोकसभा चुनाव । फिलहाल नई सरकार को बधाई और शुभकामनाए । 'अरुण -विष्णु-विजय भव'

जाति,अपमान और मिमिक्री की राजनीति

महाभारत में जुआं खेलने की सहमति युधिष्ठिर ने दी. हारने पर वस्तु की तरह पत्नी को दांव पर लगाने का काम युधिष्ठिर ने किया. सारा दोष दुशासन को दिया गया. युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दे दी गई. रामायण में शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी लेकिन सारा दोष रावण के सिर मढ़ दिया गया. इसी तरह से अहिल्या के साथ हुआ. उन के साथ छल इंद्र ने किया और पत्थर अहिल्या को बनना पडा. पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरणों की भरमार है.

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर धनखड़ की मिमिक्री कर दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस का वीडियो बनाया. भाजपा ने इस को मुददा बना दिया. इसे देश के संवैधानिक पद के अपमान से जोड़ दिया गया है. इस मसले को ले कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में जिस तरह से अपनी बात रखी उस से लगा कि वे बेहद आहत हैं.

प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बात करते हुए उन को सांत्वना देते कहा, 'पिछले 20 सालों में मैं खुद लगातार अपमान सहन कर रहा हूं.' प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब पूरी पार्टी, संगठन और सोशल मीडिया टीम 'मिमिक्री कांड' को विक्टिम कार्ड के रूप में खेल रही है

भाजपा ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाति से जोड़ कर बड़ा दांव चल दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे हैं. इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. कांग्रेस इस मुद्दे को उठा कर बीजेपी के ओबीसी वोटबैंक में सेंध लगाने की कोशिश में थी. अब भाजपा ने उपराष्ट्रपति के अपमान को ओबीसी से जोड़ कर अपने वोटर को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है.

भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पिछडा नेता कहती है. केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्यसभा में कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है. ये लोग बारबार संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपमानित करते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी को 20 साल तक अपमानित किया. चूंकि वे गरीब तबके से आते थे, ओबीसी थे, इसलिए वे ऐसा करते थे. पीएम बनने के बाद भी उन को अपमानित किया गया. राष्ट्रपति को अपमानित किया क्योंकि वे अनुसूचित जनजाति के हैं. अब किसानपुत्र और जाट समाज का भी अपमान किया गया है. विपक्ष उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहा है. उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान.पौराणिक कथाओं पर चलने वाली भाजपा उन्हीं कहानियों के बताए अनुसार चल रही है. महाभारत में जुआं खेलने की सहमति युधिष्ठिर ने दी. हारने पर वस्तु की तरह पत्नी को दांव पर लगाने का काम युधिष्ठिर ने किया. सारा दोष दुशासन को दिया गया. युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि दे दी गई. रामायण में शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी लेकिन सारा दोष रावण के सिर मढ़ दिया गया. इसी तरह से अहिल्या के साथ हुआ. उन के साथ छल इंद्र ने किया और पत्थर अहिल्या को बनना पडा. पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरणों की भरमार है.

इसी तरह से भाजपा भी 'मिमिक्री कांड' को ले कर कर सकती है. ओबीसी की गोलबंदी करने के लिए भाजपा 'मिमिक्री कांड' को एक हथियार की तरह से प्रयोग कर रही है. भाजपा के इस दांव से विपक्ष बैकफुट पर आ गया है. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि उन का मकसद किसी को आहत करना नहीं था. वे मिमिक्री को आर्ट से जोड़ रहे हैं. इस के बाद भी भाजपा ने छोटे बड़े हर स्तर पर 'मिमिक्री कांड' को ओबीसी के सम्मान से जोड़ दिया है.

मन,शरीर और रोग

डॉ अनिल गुप्ता

अधिकांश लोग, या तो अंतर्बोध या फिर अपने निजी अनुभव के आधार पर, यह मानते हैं कि भावनात्मक तनाव भी गंभीर शारीरिक रोगों को उत्पन्न कर सकता है या उनके आगे बढ़ने की दिशा को बदल सकता है। ये तनाव किस तरह क्रिया करते हैं, यह अभी स्पष्ट नहीं है,लेकिन यह स्पष्ट है कि भावनाओं से कुछ शारीरिक क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं, जैसे हृदय गति, ब्लड प्रेशर, पसीना आना, सोने के तरीके, पेट में अम्ल का स्राव, और आंत्र क्रियाएं, लेकिन इसके अन्य संबंध कम स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा तंत्र। उल्लेखनीय है कि मस्तिष्क की गतिविधि को बदलकरइम्यून सिस्टम की प्रक्रिया को परिवर्तित कियाजा सकता है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स या लिम्फ वेसल्स के माध्यम से शरीर में संचरण करती हैं और ये तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। इसके बावजूद, शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ संचार करता है। उदाहरण के लिए, डिप्रेशन इस प्रतिरक्षा प्रणाली को रोक सकता है और व्यक्ति को संक्रमणों जैसे सामान्य सर्दी-जुकाम के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है।

मन और शरीर एक शक्तिशाली तरीके से पारस्परिक संपर्क करते हैं जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पाचन तंत्र पूर्णतया मन (मस्तिष्क) द्वारा नियंत्रित होता है, तथा अत्यधिक चिंता, डिप्रेशन, और डर इस तंत्र की क्रिया को आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करते हैं। सामाजिक और मानसिक तनाव व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के रोगों और विकारों को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे डायबिटीज मैलिटस, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, और माइग्रेन सिरदर्द। हालांकि, मनोवैज्ञानिक कारकों की प्रासंगिक महत्ता समान विकारों से ग्रस्त अलग-अलग लोगों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होती है।

तनाव के कारण शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं भले ही व्यक्ति को कोई रोग न हो क्योंकि शरीर भावनात्मक तनाव के प्रति शारीरिक रूप से अनुक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, तनाव अत्यधिक चिंता का कारण बन सकता है, जो फिर हृदय गति को बढ़ाने और ब्लड प्रेशर और पसीने की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्वसंचालित तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन जैसे एपीनेफ़्रिन को उत्प्रेरित करती है। तनाव से मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, जिसके कारण गर्दन, पीठ, सिर, या किसी भी भाग में दर्द होता है।

मानसिक-शारीरिक चिकित्सा पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित थेराप्युटिक चिकित्सीय तकनीकोंको संदर्भित करती है कि मानसिक और भावनात्मक कारकों से शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने और रोग की रोकथाम अथवा उपचार करने का प्रयास करने के लिए व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विधियों का उपयोग किया जाता है।

मन और शरीर में इंटरैक्शन एक द्विपथीय सड़क है। मनोवैज्ञानिक कारक न केवल विभिन्न प्रकार केव्यापक शारीरिक विकारों की शुरुआत करने या वृद्धि करने में योगदान देते हैं, बल्कि इनके कारण ऐसे शारीरिक रोग भी हो सकते हैं जिनसे व्यक्ति की सोच या मनोदशा पर बुरा असर पड़ सकता है। प्राणघातक, आवर्ती, या क्रोनिक शारीरिक विकारों से ग्रस्त लोग आमतौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन के कारण शारीरिक रोग से और अधिक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और इससे व्यक्ति का दु:ख और बढ़ सकता है।

लोकसभा चुनाव पर फोकस ,क्षेत्रीय-जातीय समीकरण का विष्णु मंत्रिमंडल

बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है. पार्टी ने सरगुजा संभाग से तीन विधायकों को मंत्री बनाया है, जिसमें लक्ष्मी राजवाड़े-भटगांव, राम विचार नेताम रामानुजगंज और श्याम बिहारी जायसवाल मनेंद्रगढ़ से हैं. बस्तर के नारायणपुर से केदार कश्यप, बिलासपुर संभाग से लखन लाल देवांगन, ओ पी चौधरी हैं. दुर्ग संभाग से दयालदास बघेल, रायपुर संभाग से बृजमोहन और टंकराम वर्मा का नाम शामिल है.

राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 39 आरक्षित हैं, जिसमें 29 एसटी और 10 एससी वर्ग के लिए हैं. 51 सीटें सामान्य हैं. इनमें से भी 11 सीटों पर स्ष्ट जातीय का प्रभाव है. प्रदेश की आधी सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव ओबीसी का है. चूंकि, 47 फीसदी आबादी ओबीसी है, इसलिए एक चौथाई विधायक इसी वर्ग से आते हैं. कुल 12 मंत्रियों में 6 ओबीसी, तीन एसटी, दो सामान्य और एक एससी वर्ग के नेता को मंत्री बनाया है. इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एसटी वर्ग से आते हैं जबकि उपमुख्यमंत्री अरुण साव ओबीसी और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सामान्य कैटेगरी से आते हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के नजरिये से बीजेपी ने लोकसभा क्षेत्रों से भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है. वर्तमान में राज्य की 11 में से 9 सीट पर बीजेपी का कब्जा है.

सीएम विष्णुदेव साय की लोकसभा रायगढ़ है, रामविचार नेताम (सरगुजा), श्याम विहारी जायसवाल (कोरबा), लक्ष्मी राजवाड़े (सरगुजा), अरुण साव (बिलासपुर), ओपी चौधरी (रायगढ़), लखनलाल देवांगन (कोरबा), बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर), टंकराम वर्मा (रायपुर), विजय शर्मा (राजनांदगांव), दयालदास बघेल (दुर्ग) और केदार कश्यप (बस्तर) से आते हैं.

इस बीच, किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर भी पार्टी ने जातीय समीकरण साधने के साथ युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की है.

सिंह बस्तर सीट से पहली बार विधायक बने हैं. वो डिप्टी सीएम अरुण साव की जगह प्रदेश संगठन की कमान संभालने जा रहे. कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी. पार्टी ने राज्य में सभी वर्गों को सरकार के जरिए साधने का प्रयास किया है. राज्य बीजेपी के एक नेता ने कहा कि पार्टी प्रदेश की सभी 11 सीटों पर 2024 में चुनाव जीतेगी. बता दें कि 2014 में बीजेपी को राज्य की 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

हवा का रुख क्यों नहीं समझ पाए भूपेश, कहां चूक गई कांग्रेस?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ताज़ा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार दिया? राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पांच साल में एक के बाद एक कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ़ घोटाला जैसे आरोप, ईडी और आईटी की छापामारी, मुख्यमंत्री के क़रीबी अफ़सरों के इन आरोपों में जेल भेजे जाने जैसे मुद्दों ने भी असर डाला.

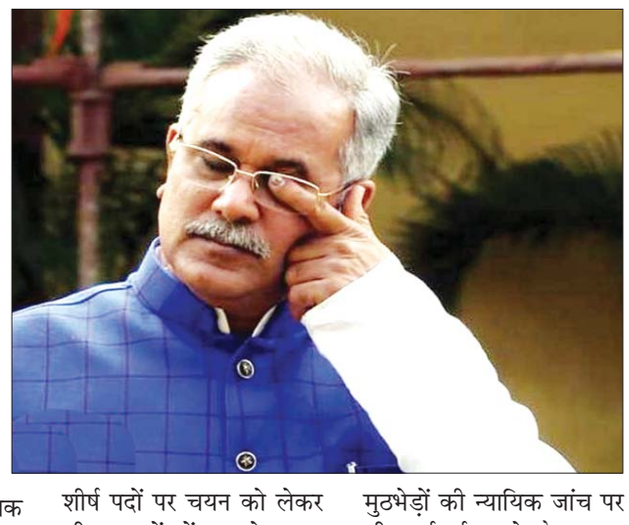

ताज़ा चुनाव में 75 पार का नारा दिया था. लेकिन हालत 2003 जैसी हो गई. ताज़ा चुनाव में कांग्रेस के अधिकांश दिग्गज़ नेता हार गए हैं. भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज़ कराई लेकिन दूसरी पार्टियों का बड़ा असर होने की संभावना धरी रह गई. हालत ये है कि पिछले चुनाव में पूरे राज्य में सर्वाधिक 59284 वोटों के अंतर से कवर्धा से जीत हासिल करने वाले मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अक़बर भी 39,592 वोटें के अंतर से चुनाव हार गए हैं. कवर्धा में पिछले दो सालों से सांप्रदायिक तनाव का वातावरण बना हुआ था. उप-मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से चुनाव हार गए हैं.

इसी तरह कवर्धा के पड़ोस की साजा सीट से, राज्य के दूसरे कद्दावर मंत्री और सरकार के दूसरे प्रवक्ता रवींद्र चौबे भी चुनाव हार गए हैं.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ताज़ा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को क्यों नकार दिया? राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि पांच साल में एक के बाद एक कोयला घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ़ घोटाला जैसे आरोप, ईडी और आईटी की छापामारी, मुख्यमंत्री के क़रीबी अफ़सरों के इन आरोपों में जेल भेजे जाने जैसे मुद्दों ने भी असर डाला. सरकार के अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार के मामले आम रहे.

यहां तक कि पीएससी में भी पीएससी अध्यक्ष के परिजनों, मुख्यमंत्री के क़रीबी अफ़सरों-नेताओं के बच्चों के शीर्ष पदों पर चयन को लेकर भी युवाओं में आक्रोश था. लेकिन सरकार इसकी जांच से भी बचने की कोशिश करती रही. उलटे इस मामले में अभियुक्तों का बचाव किया गया.

इन पांच सालों में हसदेव से लेकर सिलगेर तक दो दर्जन से अधिक जगहों पर आदिवासियों के आंदोलन चलते रहे और साल-साल भर तक चलने वाले इन आंदोलनों की सरकार ने न केवल अनदेखी की, कुछ इलाकों में तो इन आंदोलनों का दमन भी किया गया. बस्तर में हुए फर्ज़ी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच पर भी कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया.

इसके अलावा भूपेश बघेल ने पांच साल मुख्यमंत्री रहने के चक्कर में पार्टी को कई टुकड़ों में बांट दिया था. मंत्रियों के पर कतर दिए गए थे. विधायकों के काम नहीं हो पा रहे थे. विधायकों के ख़िलाफ़ अलोकप्रियता थी. यही कारण है कि पार्टी ने 71 में से 20 विधायकों की टिकट ताज़ा चुनाव में काट दी थी. लेकिन यह भी काम नहीं आया.

तीनो पूर्व मुख्यमन्त्रियो ने बगावत क्यों नहीं की ?

तीन राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी के तीन बड़े नेता किनारे लग गए. छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बता दिया गया कि उनकी राजनीति अब यहीं तक थी. हालांकि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य अब भी बीच में फंसा है. ऐसे में एक सवाल और उठ रहा कि आखिर एमपी-राजस्थान में सीएम नहीं बनाए जाने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ने बगावत क्यों नहीं कीं. तीन राज्यों के तीन नए मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिसमें कहा गया कि अगर इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हुई होती और कांग्रेस के स्थापित नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर पार्टी टूटकर कई धड़ों में बिखर गई होती.

पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी इसके साक्षात उदाहरण हैं. इन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई और अब अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी में इसका ठीक उल्टा है.

बीजेपी में जितने भी कद्दावर नेता बागी हुए, बगावत के बाद या तो उन्हें फिर से बीजेपी की ही शरण में आना पड़ा या फिर राजनीति में वो ऐसे हाशिए पर गए कि उन्हें सियासत से संन्यास ही लेना पड़ा. गुजरात में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं. साल 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो 2002 चुनाव में उन्हें विधानसभा का टिकट तक नहीं मिला. हालांकि राज्य सभा के जरिए वो केंद्र की राजनीति में गए. लेकिन 2007 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की.

उन्होंने तब बीजेपी की अपनी सदस्यता भी रिन्यू नहीं करवाई और साल 2012 में बीजेपी छोड़कर नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई. उस चुनाव में अपनी पार्टी से जीतने वाले वो एकलौते विधायक थे. तब उन्होंने विसवदर विधानसभा से बीजेपी के कनुभाई भलाला को मात दी थी.

जब ये तय हो गया कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब गुजरात नहीं, बल्कि दिल्ली संभालेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे तो केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ कर दिया. एक लाइन में कहें तो बीजेपी से उनकी बगावत उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर गई.

कल्याण सिंह ने बगावत कर बना ली थी पार्टी

बीजेपी के बागियों की फेहरिश्त में बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का भी है. उस समय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी हुआ करते थे. साल 1999 में कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था,

जिसके बाद कल्याण सिंह ने बगावत कर अपनी नई पार्टी बनाई और उनका नाम राष्ट्रीय क्रांति पार्टी रखा.

हालांकि तीन साल में ही कल्याण सिंह को समझ में आ गया कि नई पार्टी के बल पर वो राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर सकते तो 2004 में उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली. उन्होंने उस समय लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए, लेकिन 2009 में उन्होंने फिर से बीजेपी छोड़ दी.

उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी का समर्थन किया. कल्याण सिंह के बेटे राजवीर तो सपा में शामिल ही हो गए और 2009 में एटा से सपा के समर्थन से निर्दलीय सांसद बने. इसके बाद मुलायम सिंह यादव से उनकी अनबन हुई तो अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम जन क्रांति पार्टी रखा, लेकिन 2014 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए.

बेटे को बीजेपी ने सांसद बना दिया और कल्याण सिंह को राज्यपाल बनाया. बगावत की सियासत देखें तो साफ दिखता है कि बागी होकर कल्याण सिंह को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के साथ आए तो बेटे सांसद बने और खुद वो राज्यपाल बन गए.

उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी के किस्से

मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं उमा भारती की बगावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली उमा भारती मुख्यमंत्री तो बनीं, लेकिन एक साल के अंदर ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई. 10 पुराने एक मामले में जब उनकी गिरफ्तारी

तय हो गई, तो अगस्त 2004 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा.

कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी दफ्तर में लाल कृष्ण आडवाणी से झगड़ा होने के बाद उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया. हालांकि संघ के हस्तक्षेप से उमा भारती का निलंबन रद्द हो गया, लेकिन वह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाए रहीं. उनकी एक ही मांग थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए. केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं था, नतीजा यह निकला कि उमा भारती को फिर से पार्टी से निकाल दिया गया.इसके बाद उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई नई पार्टी बनाई और दावा किया कि उनकी पार्टी संघ की विचारधारा पर चलेगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का उनकी पार्टी को समर्थन है, लेकिन इस पार्टी की बदौलत उमा भारती को कुछ भी हासिल नहीं हुआ.

मजबूरी में उमा भारती जून 2011 में फिर से बीजेपी में लौट आईं और फिर 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया. 2014 में उमा भारती सांसद बनीं और फिर मोदी सरकार में मंत्री भी बनाई गईं. वो अब भी बीजेपी में ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बगावत से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होना है.

बाबू लाल मरांडी ने भी की थी बगवात

झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं. वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं. मुख्यमंत्री पद से हटने और 2004 में सांसद बनने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए और साल 2006 में बीजेपी से अलग होकर उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के नाम से नई पार्टी बनाई.

2009 में वे अपनी पार्टी से सांसद भी बने, लेकिन 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीति के केंद्र में आने के साथ ही बाबू लाल मरांडी की सियासत भी कगार की ओर बढ़ गई. साल 2020 में बाबू लाल मरांडी ने बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया और अब वो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं.

येदियुरप्पा को देना पड़ा था इस्तीफा

बीजेपी के ही एक और बागी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कोई कैसे भूल सकता है. ये वही बीएस येदियुरप्पा हैं, जिन्होंने साइकल चला-चलाकर कर्नाटक में बीजेपी को मजबूत किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे.

लोकायुक्त की जांच में दोषी साबित होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. इस इस्तीफे के लिए मनाने में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू तक को पसीना आ गया था. हालांकि येदियुरप्पा का इस्तीफा भी हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा. 25 दिनों के बाद वो जेल से बाहर आए और बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी.

उन्होंने अपनी नई पार्टी तक बनाई, लेकिन मोदी युग के दौरान फिर से बीजेपी में चले गए. पहले सांसद और फिर मुख्यमंत्री बने. अब उनकी विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं जो कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं.

कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार बीएस येदियुरप्पा के ही खास थे. येदियुरप्पा ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए और कांग्रेस में चले गए. उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस की लहर में भी हार गए. मजबूरी में कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना रखा है. जाहिर है कि बगावत का कुछ खास फायदा जगदीश शेट्टार को नहीं हुआ. कुछ यही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदनलाल खुराना का भी रहा था.

दिल्ली के सीएम को बीजेपी ने पार्टी से निकाला था

दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मदनलाल खुराना को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन वो बार-बार केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर से बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए ही रहे.

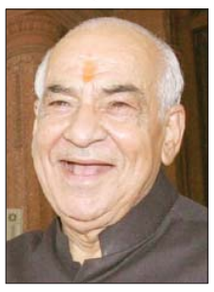

नतीजा ये हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया. हालांकि वो बीजेपी में वापस भी आए, लेकिन तेवर ऐसे ही रहे और फिर दूसरी बार जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला तो राजनीति में उनकी कभी वापसी हो ही नहीं पाई. अब ये बगावत की जितनी भी कहानियां हैं, वो सिर्फ किताबों में ही दर्ज नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के वो तमाम नेता इन कहानियों को जानते हैं, जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां एक-एक करके चढ़ी हैं. चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, वसुंधरा राजे सिंधिया हों या फिर रमन सिंह हों,उन्हें पता है कि बीजेपी से बगावत करने वालों को हासिल कुछ भी नहीं होता है. हां अगर बीजेपी के साथ बने रहें तो सांसद बनने से लेकर केंद्र में मंत्री या फिर किसी प्रदेश का राज्यपाल बनने का अवसर उनके पास हमेशा ही रहेगा.

पार्टी सिम्बल से ज्यादा मजबूत एक चेहरा

परंतु आश्चर्य है की जो नरेन्द्र मोदी स्वयं पार्टी सिम्बल की बजाय एक मजबूत चेहरा बनकर चुनाव जीतने का पुरजोर समर्थन कर चुके हों, उनके समर्थक उसको सही भी ठहराते है,तो वही मोदी राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहते।

भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है जहाँ दल अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। जो दल जीतता है वह अपने जीते हुए विधायकों या सांसदों द्वारा अपने दल का नेता चुनता है। इसके बाद वही चुना हुआ नेता राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके बहुमत के दावे को परखते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद सरकार बनाने का न्यौता देते हैं।

ये बातें सैद्धांतिक रूप में लागू तो हैं लेकिन औपचारिक रूप से इसकी खानापूर्ति की जाती है। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक यात्रा देखें तो पार्टी सिम्बल से अधिक नेता ही पार्टी का चेहरा बनते आये हैं। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक जवाहरलाल नेहरु कांग्रेस की पहचान रहे। 1951 से 1971 कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था। 1971 से 1977 तक गाय बछड़ा इंदिरा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था।1977 के बाद से हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव निशान है। लेकिन इन 73 सालों में कांग्रेस के नेताओं से ही कांग्रेस की पहचान होती रही।

उसकी पहचान कभी नेहरु से, कभी इंदिरा से तो कभी राजीव गांधी से होती रही। 1991 में राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद कुछ साल के लिए नेहरु वंश का प्रभाव कांग्रेस में कम हुआ लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद से कांग्रेस की पहचान एक बार फिर नेहरु-गांधी वंश बन गया।

दूसरी ओर विपक्ष में जनसंघ का उदय देश के पहले आमचुनाव 1951 के समय में ही हो गया था। 1951 से 1977 तक जनसंघ का चुनाव निशान जलता दीपक रहा और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी बन जाने के बाद कमल का फूल बन गया। जनसंघ हो या भाजपा इसमें किसी एक परिवार का प्रभुत्व कभी नहीं रहा और यह संगठन आधारित दल बना लेकिन इसकी पहचान भी इसके शीर्ष नेताओं से ही होती थी। शुरुआत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और फिर अटल बिहारी वाजपेयी। नब्बे के दशक में जब कांग्रेस किसी नेहरुवंश वाले चेहरे के अभाव में थी और अन्य दल भी नये नये चेहरों के साथ मैदान में थे तब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। नब्बे के दशक में उनकी स्वीकार्यता सर्वाधिक थी और इसका लाभ भी भाजपा को मिला। 1996 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार प्रधानमंत्री बने और एक बार अपना कार्यकाल भी पूरा किया। लेकिन 2014 में नरेन्द्र मोदी के उभार ने अब तक के सारे चेहरों को धूमिल कर दिया। 2013 में भाजपा के भीतर यह बहस बहुत हुई कि क्या पार्टी लाइन से अलग हटकर चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए? भाजपा में इसे लेकर विरोधाभास तो था लेकिन मोदी के आक्रामक प्रचार और सोशल मीडिया के व्यापक इस्तेमाल से वो स्वयं 'सर्वाधिक लोकप्रिय' नेता बन गये। 2014 में चुनाव जीतने के बाद जब बीजेपी पार्लियामेन्ट्री बोर्ड ने उन्हें अपना नेता घोषित किया तब वह महज एक औपचारिकता भर थी।

परंतु आश्चर्य है की जो नरेन्द्र मोदी स्वयं पार्टी सिम्बल की बजाय एक मजबूत चेहरा बनकर चुनाव जीतने का पुरजोर समर्थन कर चुके हों, उनके समर्थक उसको सही भी ठहराते है,तो वही मोदी राज्यों में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ और राजस्थान तीनों ही जगह भाजपा सामूहिक नेतृत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि अगर यह फार्मूला राज्यों पर लागू हो सकता है तो फिर केन्द्र में भाजपा किसी चेहरे पर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? संभवत: भाजपा के पास इस सवाल का जवाब यह होगा कि उनके पास लोकसभा से लेकर ग्रामसभा चुनाव तक एक चेहरा है तो किसी और की जरूरत क्या है।

लेकिन संगठन आधारित बीजेपी से उलट कांग्रेस पूरी तरह से नेता आधारित पार्टी है। इंदिरा गांधी ने एक दौर में क्षेत्रीय क्षत्रपों को ठिकाने लगाया था जिसका परिणाम कांग्रेस को आज तक भोगना पड़ रहा है। इसलिए केन्द्र में अगर नेहरुवंश कांग्रेस की पहचान है तो राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रप उसको संभालकर रखते हैं।

विपक्ष का चेहरा कौन

गिरिधर झा

तीन हिंदीभाषी प्रदेशों- मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। इस जीत से यह धारणा मजबूत हुई है कि चुनावी मैदान में 'ब्रांड मोदी' ही पार्टी का तुरुप का इक्का है। भाजपा भले ही अपने आप को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती रही हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में अधिकतर मतदाता मोदी के नाम पर ही पार्टी को वोट देते हैं। इससे न सिर्फ अधिकतर राजनैतिक विश्लेषक, बल्कि उनके धुर विरोधी भी इत्तेफाक रखते हैं। उनके सियासी प्रतिद्वंद्वी आज खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार की जीत भाजपा या आरएसएस की नहीं, बल्कि मोदी की है।

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पार्टी या पार्टी की विचारधारा पर किसी नेता विशेष के व्यक्तित्व का भारी पड़ना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में नेहरू और इंदिरा गांधी से लेकर माकपा में ज्योति बसु और तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी तक कई ऐसे कद्दावर नेता हुए जिनकी शख्सियत उनकी पार्टी से बड़ी बन गई। आज भी नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जैसे अनेक नेता हैं जिनकी पार्टी का भूत, वर्तमान और भविष्य जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता से सीधा जुड़ा है, न कि उनके दलों की विचारधारा से। जहां तक भाजपा का सवाल है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी युग से लेकर मोदी के दौर तक संगठन या सरकार में पार्टी की विचारधारा को ही सर्वोपरि समझा जाता रहा है। यह बात और है कि मोदी के शासनकाल से पहले भाजपा को अपने बल पर बहुमत कभी नहीं मिला था। अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उसे सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ता था। 2014 के बाद पार्टी अपने बूते सरकार बनाने में सक्षम हुई। उसके बाद मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो भाजपा के एजेंडे पर लंबे समय से लंबित थे। उनके कई निर्णयों की आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने किया वही जो उनकी पार्टी की नीतियों के अनुरूप था।

अगर ताजा चुनावों में वाकई तीन राज्यों के मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ मोदी के नाम पर भाजपा को सत्ता सौंपी है, तो यह प्रतिपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए जिसे जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने इन्हीं तीन

क्या 2024 के चुनावी समर के लिए विपक्ष बिना किसी नेतृत्व के चुनाव लड़ेगा? भाजपा की कमान तो एक बार फिर मोदी के हाथों में होगी, लेकिन 'इंडिया' कुनबे का सिपहसालार कौन होगा? ताजा चुनाव परिणामों ने इस सवाल को और पेचीदा बना

राज्यों में शानदार प्रदर्शन कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वहां जीत का सेहरा अपने नाम कर लिया। उस समय कहा गया कि आम मतदाता प्रदेश के चुनावों में तो स्थानीय मुद्दों के आधार पर सरकार चुनता है, लेकिन जब संसदीय चुनाव होते हैं तो उसे मोदी के अलावा कोई और विकल्प नहीं नजर आता है। इस चुनाव में यह धारणा भी टूट गई।

यह अपने आप नहीं हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता यह कहते रहे कि भाजपा की खराब स्थिति को देखते हुए मोदी को इन राज्यों में ताबड़तोड़ सभाएं करने को मजबूर होना पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में डटे रहे। इसके विपरीत, हाल के दशकों में कांग्रेस में यह परंपरा-सी बन गई है कि प्रदेश के चुनावों की बागडोर स्थानीय क्षत्रपों के हाथों सौंप दी जाती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी दूरी बना लेता है। दरअसल, मोदी तकरीबन हर चुनाव में अपनी सक्रियता दिखाते रहे हैं, उन राज्यों में भी जहां पार्टी की सफलता की गुंजाइश कम दिखती है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आने से भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ गई थी, लेकिन मोदी कई सप्ताह तक चुनावी रैलियां संबोधित करते रहे। प्रधानमंत्री के रूप में राज्यों के चुनावों के दौरान इस तरह की सक्रियता भले ही उनकी पार्टी की जीत का एकमात्र कारण न हो, लेकिन इससे भाजपा को निस्?संदेह अपनी जमीन व्यापक स्तर पर मजबूत करने में मदद मिली है। इससे यह भी पता चलता है कि मोदी के लिए हर चुनाव कितना महत्वपूर्ण है।

अगले चार-पांच महीनों के भीतर विपक्ष के लिए 'ब्रांड मोदी' की काट ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के भीतर आज भी इस बात पर संशय बरकरार है कि क्या राहुल गांधी साझा विपक्ष के सर्वमान्य नेता होंगे। कांग्रेस को शायद उम्मीद थी कि तीन राज्यों के साथ तेलंगाना में चुनाव जीतकर वह अपनी सहयोगी पार्टियों को इस बात पर राजी कर लेगी कि वे राहुल गांधी को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे करें। अब समाजवादी पार्टी और जनता दल-यूनाइटेड ने हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ते हुए साफ कह दिया है कि सहयोगी पार्टियों की उपेक्षा हुई है।

इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या 2024 के चुनावी समर के लिए विपक्ष बिना किसी नेतृत्व के चुनाव लड़ेगा? भाजपा की कमान तो एक बार फिर मोदी के हाथों में होगी, लेकिन 'इंडिया' कुनबे का सिपहसालार कौन होगा? ताजा चुनाव परिणामों ने इस सवाल को और पेचीदा बना दिया है

पत्रकारिता में एआई का प्रयोग घातक

कार्यरत लोगों का जा सकता है जॉब

पत्रकारिता! भारत के आजादी का एक अमिट इतिहास है. लेकिन, बदलते समय के साथ सब कछ बदल जाता हैं, और ऐसे में हमारा पत्रकारिता भी बदल गया है. पत्रकारिता में हमने न्यूज़ रिडर से नयूज़ एंकर तक का सफर भी तय किया, और अब तो पत्रकारिता में न्यूज़ जीपीटी और एआई न्यूज़ एंकर जैसे तकनिकों का प्रयोग शुरु हो चुका हैं. इसकी शुरआत इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव से हुई जहां आज तक ने एआई न्यूज एंकर सना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत किया. अब आप ये सोच रहे होंगे की एआई न्यूज एंकर सना का सबसे पहला डब्यू कब हुआ और कहां हुआ?...

आपको बता दें कि एंकर सना ने अपना पहला डेब्यू आज तक के ब्लैक एंड वाइट शो में सुधीर चौधरी के साथ किया और अब तो ये हर रोज सुधीर चौधरी के साथ दिखती भी है. सना हर रोज बड़ी खबरों को बताती हैं. अब दर्शकों को ब्लैक एंड व्हाइट शो में एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है, जहां वर्चुअल और ह्यूमन एंकर की जोड़ी एक साथ दिख रही है.

एंकर सना 24 भाषाओं में न्यूज़ को प्रेजेंट कर सकती हैं

एंकर सना 24 भाषाओं में समाचार को प्रस्तत कर सकती हैं. सना एक कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल एंकर है. इस एंकर की आवाज बिलकुल मानव जैसी है और दिखती भी बिल्कुल मानव की तरह हीं हैं. लेकिन यह पूरी तरह से कंप्यूटर और एआई से निर्मित है. सना अब एक ऐसी एंकर बन चुकी है, जो न सिर्फ टेलीविजन पर न्यूज़ को पढ़ती है बल्कि सना का तो सोशल मीडिया अकाउंट तक बन चुका है. वह इंस्टाग्राम से ट्विटर तक राज कर रही है. एक तरफ सना अपने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस लुक से लोगों को लुभा रही है, तो वही दूसरी तरफ ट्विटर पर वह हर खबर की अपडेट दे रही है. 18 मार्च को जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सना को प्रेजेंट किया गया तभी सना का इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट भी बन गया, और अकाउंट बनते ही सना को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यदा फेम मिलने लगा है.

नवीन प्रौद्योगिकी का भविष्य है एआई

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवीन प्रौद्योगिकी का भविष्य है. हम इसका उपयोग मीडिया के अलावा कई क्षेत्रों में कर रहें हैं. एआई ने मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया को काफी हद तक बदल दिया है. इसने दर्शकों को लक्षित करने से लेकर उनकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने तक को सुव्यवस्थित किया है. इसने सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग को काफी हद तक बदल दिया है. वर्तमान में सोशल मीडिया के उपयोग में एआई निम्नलिखित प्लेटफॉर्म पर अपने चरम पर है. इनमें फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर और कू जैसे प्लेटफर्म शामिल हैं. एआई से निश्चित रूप से देश के मीडिया में बड़ा बदलाव आएगा और व्यापार अर्थव्यवस्था का भी विस्तार होगा. एआई मीडिया व्यापार को गति प्रदान करने वाला है.

ऑटोमेशन की वजह से जा सकती हैं लोगों की जॉब

इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एआई का उपयोग देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों में किया जा रहा हैं. जिसके वजह से भारत में 69त्न और चाइना में 77त्न ऑटोमेशन की वजह से लोग अपने जॉब को गवा सकते हैं. अगर ऑटोमेशन हमारी नेसेसिटीज है, तो साथ में हम लोगों को प्रिपेयर भी रहना होगा. ऑटोमेशन के वजह से ह्यूमन को एडवांस ट्रेनिंग की भी जरूरत है. क्योंकि, जो ट्रेट एआई में डाले जाते हैं वह एक एडवांस माइंड के ह्यूमन ही प्रोग्रामिंग कर सकता हैं. इंडिया एआई के मामले में 9वें पोजीशन पर है, जहां एआईए स्पेशलिस्ट, वर्कस् फील्ड में काम कर रहे हैं. यूएस, चाइना और यूके की बात करें तो वह अभी भी टॉप पोजीशन पर है.

इंडियन जीडीपी में 1.3% का होगा ग्रोथ

सीबीएसई ने तो अपने करिकुलम में भी एआई को ऐड कर दिया है. भविष्य की मांग को देखते हुए. आईआईटी हैदराबाद ने तो फुल कोर्स बीटेक का एआई पर ही स्टार्ट कर दिया है. मैकिन्से की रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में .13 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इकनोमिक ग्रोथ 2030 तक हो जाएगा और ग्लोबल जीडीपी में सालाना 1.2% की बढ़ोतरी होगी वही भारत की बात करें तो 957 बिलियन डॉलर इंडियन जीडीपी में उछाल आएगा या ऐसे कहें 1.3त्न का ग्रोथ होगा.

300 मिलियन लेगों का जॉब खतरे में

हाल हीं में गोल्डमैन सैच्स की आई रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि बढ़ते एआई के प्रयोग के कारण 300 मिलियन लेगों का जॉब खतरे में पड़ सकता हैं. इसका मतलब ये है कि 300 निलियन कार्यरत लोगों की जगह एआई ले लेगा. लेकिन जेनेरेटिव एआई सिस्टम चाट जीपीटी, न्यूज़ जीपीटी और एआई न्यूज़ एंकर जैसे टेक्नोलॉजी आने के बाद एम्प्लाइज का जॉब जाने का खतरा सच में बढ़ गया है. अब देखना यह होगा कि क्या एआई सिर्फ आईटी कंपनियों का जॉब रिप्लेस करेगा या फिर नॉन आईटी कंपनियों पर भी अपना असर दिखाएगा.

दांत खाने की ही नही दिखाने के भी

डॉ. सुजीत परिहार
बीडीएस, एमआईडीए
मो.नं. 7000414949

सुन्दर दांतों की चाहत सभी को होती है लेकिन कुछ लोगो के दांत टेढ़े मेढ़े होते है,दांतों का अलाइनमेंट सही नहीं होता है। दांतों के बीच में काफी खुली हुई जगह होती है। इस तरह की स्थितियों अक्सर लोगों की निगाह जमी रहती है. लोगों को ब्रश करने,भोजन करने और ठीक से चबाने में तकलीफ देता है। जिसकी वजह से उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग यदि अपने दांतों की उचित देखभाल नहीं करते तो सामन्य लोगो की तुलना में इन लोगो के दांतों की सडन की समस्या का खतरा ज्यादा होता है। प्रसिद्ध दंतरोग विशेषग्य सर्जन डॉ सुजीत परिहार ने लाईफ वर्सिटी से बात करते हुए बताया की अक्सर बचपन के दूध वाले दांत सही आते है लेकिन परमानेंट निकलने वाले दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते है। जिसका प्रमुख कारण इनका ठीक से देखभाल न करना हो सकता है। हालाँकि कुछ कारण अनुवाशिक भी होते है। डॉ सुजीत बताते हैं कि टेढ़े मेढ़े दांत बैक्टेरिया

के बढ़ने को अवसर प्रदान करते है जिससे प्लांक निर्मित होता है और साँसों से दुर्गन्ध आती है, मसूढ़ों की दांतों पर पकड कमजोर हो जाती है। टेढ़े मेढ़े दांतों के मध्य अक्सर दरार रहता है फलत: खाते और चबाते समय दांत आपस में रगड़ खाकर कमजोर पड जाते है। टेढ़े दांतों की समस्या किसी को भी हो सकती है। मुख्य रूप से अगर दूध के दांत गिरने के बाद स्थायी दांत आसान तरीके से निकलते हैं। उपचार के लिए कोई विशेष आयु बाधा नहीं है। टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज 2-3 तरीकों से हो सकता है. सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है दांतों पर तार लगवाना. जिसको ब्रेसेस बोलते हैं। ब्रेसेस टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक कर मुख की सुन्दरता बढाने में मदद करते है तार 2-3 तरह से लगते हैं। ये मेटल ब्रेसेस, सेरामिक ब्रेसेस, इनविजिलाइन अलाइनर्स. बच्चों को ब्रेसेस लगवाने की सबसे सही उम्र 12-14 साल होती है। तब दूध के दांत सारे टूट जाते हैं और पक्के दांत सारे आ जाते हैं। इस समय हड्डियों में भी लचीलापन होता है. इस समय दांत बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। 40 साल की उम्र तक दांतों का टेढ़ापन ठीक किया जा सकता है. अलाइनर्स बड़े लोगों के लिए एक अच्छा इलाज है। अलाइनर्स ज़्यादा दिखाई नहीं देते।

उभरी हुई नसे वेरिकोस वेन्स हो सकती है

डॉ संस्कृति सिंह
डाईट एवं लाईफ स्टाइल मेडिसिन
पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन
रायपुर

वेरिकोस वेन्स हमेशा सूजी और उभरी हुई नशो के रूप मे बाहर आता हैं और ये नीले और लाल रंग के होते है नशे बड़ी चौड़ी या उसमे रक्त ज्यादा भर जाता है तथा जिनमे अक्सर दर्द महसूस होता हैं वेरिकोस वेन्स कहलाता है इसे वेरिकोस साईटिक भी कहा जाता है लगभग 25-30त्न लोग वेरिकोस वेन्स की समस्या से ग्रस्त है वेरिकोस वेन्स दोनों पैरो मे ज्यादा दिखाई देते है

यह एक गंभीर समस्या है जिसको समय रहते उचित जांच एवं इलाज की आवश्यकता है नशो मे वाल्व मौजूद होते है जिनको काम खून को शरीर के दूसरे हिस्से से दिल तक ले जाना है लेकिन कुछ कारणों से वाल्व खराब हो जाते हैं या अपना काम सही से नही करते है तो खून दिल तक जाने की बचाये नशो मे ही एक जगह जमा होने लगती है और वेरिकोस वेन्स को जन्म देती हैं

ये शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है ये ज्यादातर पैरो मे देखा जाता हैं क्युकि शरीर का सारा भार पैरो मे होता है

ये शरीर के बाहर साफ साफ दिखाई देते हैं इसमें सुजन और जलन होता हैं

लक्षण –

1 पैरो मे अक्सर दर्द होना
2 नशो का साफ साफ दिखना
3 सूजन एवं जलन होना
4 भारीपन एवं ऐठन
गंभीर मामलों मे नशो से खून आना या अल्सर बन जाना

कारण –

प्रेग्नेंसी, मेनुपल्स, 50 से अधिक उम्र, लंबे समय तक खड़े रहना, पैर लटका कर खुर्सी मे बैठना, टाइट जिन्स पहनना , टाइट बेल्ट लगाना , शारीरिक श्रम ना करना

योग एवम प्राकृतिक चिकित्सा

1 Mude therepy
2 Eyes massage
3 नियमित व्याम करना जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहे
4 चलना, तेराकी, टखना व्याम, साइकिल चलाना. 5 ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना. 6 कम्प्रेशन स्टैकिंग का इस्तेमाल करना . फ्लेवनोएडल युक्त आहार लेना.
7 sun bath

इनसे बचें –

वजन ना उठायें
अत्यधिक दोड़ने से बचे

वेरिकोस वेन्स के प्रकार –

1 स्फीनस् वेरिकोस वेन्स
2 जलिदार वेरिकोस वेन्स
3 स्पाइडर वेरिकोस वेन्स

वेरिकोस वेन्स का उचित आहार

चुकन्दर , अंगूर, अदरक, चेरिस , हल्दी, अंकुरित आहार, सेब, हरी पत्तेदार सब्जियां,

हार्ट अटैक ही नहीं अब लंग्स अटैक का भी बढ़ रहा खतरा

डॉ. बालाकृष्णा
सीनियर चेस्ट फिजिशियन, इन्टेनसिविस्ट एंड स्लीप मेडिसीन स्पेशलिस्ट, 8109161700

फेफड़े की बीमारी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है. प्रदूषण, धूम्रपान, नजला आदि के कारण फेफड़ों की बीमारी बहुत आम होती जा रही है. पहले सिर्फ हार्ट अटैक के बारे में सुनाई देता था लेकिन अब फेफड़ों के अटैक की खबर भी खूब सुनाई देने लगी है, जो लोगों की असमय मौत का दूसरा बड़ा कारण बन रहा है. 2020 में प्रकाशित डब्लूएचओ के आंकड़ों के अनुसार भारत में 879,732 लोगों की मौत लंग्स की बीमारियों के चलते हुई जो कि कुल मौत का 10.38 प्रतिशत है. भारत इस मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है.

फेफड़े हमारे शरीर में औक्सीजन का संचार करते हैं. ये खून को शुद्ध करते हैं और सांस को फिल्टर करते हैं. यदि किसी व्यक्ति के फेफड़े में वायरस, बैक्टीरिया या फंगस विकसित हो जाएं तो फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं. फेफड़े जिन छोटीछोटी थैलीनुमा संरचनाओं से मिल कर बने होते हैं उन में संक्रमण के चलते मवाद जमा होने लगता है. इस से सूजन होने लगती है और सांस लेने में दिक्कत होती है. इसे ही लंग इन्फैक्शन कहते हैं. इस की वजह से निमोनिया हो जाता है. जब यह संक्रमण बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो यह ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी में बदल जाता है. फेफड़े की बीमारी पर शुरू में ही ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है वरना यह बीमारी टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस भी बन सकती है.

क्रोनिक औब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) के मरीजों में फेफड़ों का अटैक पड़ने की संभावना बहुत अधिक होती है. सीओपीडी फेफड़ों की एक बीमारी है जो फेफड़ों में हवा के प्रवाह को रोकती है. इस बीमारी में फेफड़ों में सूजन आ जाती है. इस के परिणामस्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, अतिरिक्त म्यूकस बनना, खांसी और अन्य समस्याएं होती हैं. करीब 20 वर्षों पहले तक सीओपीडी को विदेशी डाक्टर्स धूम्रपान से होने वाली बीमारी मानते थे लेकिन मौजूदा समय में यह बीमारी उन लोगों में भी देखी जा रही है जो धूम्रपान नहीं करते.

लकड़ी और कंडे की आग पर खाना बनाने वाली महिलाओं में यह बीमारी देखी गई है. वहीं कांच और पत्थर का काम करने वाले मजदूरों में, संगमरमर की घिसाई करने वाले कारीगरों में, कार मेकैनिक जो कार आदि की पेंटिंग का काम करते हैं, आदि सभी में फेफड़ों से जुड़ी क्रोनिक बीमारियां देखी जा रही हैं. यातायात पुलिस के वे कौंस्टेबल्स जो बड़े चौराहों पर दिनभर ट्रैफिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, अकसर फेफड़े के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं.

लंग अटैक की समस्या फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों के कारण होती है. लंग अटैक की समस्या होने पर मरीजों में ये लक्षण प्रमुखता से देखे जाते हैं–

अत्यधिक खांसी विशेषकर बलगम के साथ.

सांस लेने में कठिनाई.

हलके व्यायाम या शारीरिक गतिविधि करते समय सांस की दिक्कत.

घरघराहट.

चलने में समस्या.

हर समय अधिक थका हुआ महसूस करना.

बलगम में खून का आना.

टखनों और पैरों में सूजन.

अचानक वजन घटना या बढ़ना.

बेचैनी, भ्रम, विस्मृति, बोलने में गड़बड़ी और चिड़चिड़ापन.

बारबार सिरदर्द और चक्कर आना.

बुखार, विशेष रूप से सर्दी या फ्लू के लक्षणों के साथ.

कोरोना महामारी का सब से ज्यादा असर लोगों के फेफड़ों पर ही हुआ है. इस महामारी से उबरने के बाद भी यह महसूस किया जा रहा है कि मौसम बदलने पर होने वाला नजलाजुकाम ठीक होने में बहुत लंबा वक्त ले रहा है. फेफड़ों में इन्फैक्शन के मुख्य कारण 2 हैं– वायरस और बैक्टीरिया.

जब हम सांस लेते हैं तो ये रोगाणु सांस के साथ हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और वहां हवा की छोटीछोटी थैलियों में जमा हो जाते हैं. इस के बाद इन की संख्या बढ़ने लगती है और फिर ये संक्रमण पैदा करते हैं. यदि समय पर उपचार न किया तो गंभीर बीमारियां हमें घेर लेती हैं.

शरीर के सभी अंगों की तरह फेफड़ों का भी पूरा खयाल रखना चाहिए. अगर फेफड़े स्वस्थ नहीं हैं तो वे औक्सीजन का अवशोषण कर शरीर के सभी अंगों को पहुंचाने में सक्षम नहीं होते. फेफड़ों के अस्वस्थ रहने से सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इस से कई बीमारियां दस्तक देती हैं. खासकर, सर्दी के दिनों में हवा की गुणवत्ता खराब रहने की वजह से सांस संबंधी बीमारियां, जैसे अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और स्ट्रोक आदि का खतरा बढ़ जाता है.

इस मौसम में वायु प्रदूषण से फेफड़े और दिल को अधिक नुकसान पहुंचता है. इस के लिए फेफड़ों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है.

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा

डॉ. विशेष गुप्ता

महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देश एवं समाज में सक्रिय विमर्श का हिस्सा नहीं बन पा रही है। ऐसा शायद इसलिए है, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाएं एक लंबे काल तक अवमानित और शोषण की शिकार रही हैं। सामाजिक परंपराओं, रीति-रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों का महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान भी कम नहीं रहा। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, अपहरण, यौन क्रूरता और उन पर तेजाब फेंकने जैसी घटनाएं आज भी सुनने और पढ़ने को मिल रही हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों में उनके साथ छेड़छाड़ की घटनाएं भी होती रहती हैं।

इस संदर्भ में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2022 की आई रिपोर्ट की मानें तो देश में महिलाओं के विरुद्ध चार प्रतिशत और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन घटनाओं से जुड़ी हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज हो रही हैं। स्पष्ट है कि स्थिति चिंताजनक है। साइबर अपराधों के मामलों में भी 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इन अपराधों का शिकार महिलाएं भी बन रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में लगातार तीन वर्षों से वृद्धि दर्ज की जा रही है। बतौर उदाहरण 2022 में महिलाओं के विरुद्ध तमाम अपराधों से जुड़े कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 एवं 2020 में क्रमश: 4,28,278 एवं 3,71,503 थे। 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 48,755 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 43,414 रहा था।

देखा जाए तो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में समाहित एक वैचारिकी रही है, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंकती है, लेकिन यह भी सच है कि जैसे-जैसे महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं, वैसे-वैसे उनके विरुद्ध हिंसा करने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगती हैं। एक ऐसे समय जब कार्य क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तब उनके खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति कानूने एवं व्यवस्था में सुधार करके ही की जा सकती है।

एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जिन राज्यों में महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों को लागू करने में जीरो टालरेंस की नीति है और विभिन्न कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहां महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध घटे हैं। उत्तर प्रदेश इसका जीता-जागता उदाहरण है। एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला संबंधी अपराधों को लेकर 2020 में 65,743 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में इनकी संख्या घटकर 56,683 रह गई। आज उत्तर प्रदेश में आरोपितों को सजा दिलाने की दर राष्ट्रीय औसत 25.3 प्रतिशत के मुकाबले 180 प्रतिशत से भी अधिक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में 70.8 प्रतिशत मामलों में आरोपितों को सजा दिलाई गई है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि के साथ यह भी सच है कि महिलाएं आज प्रगति के नए-नए लक्ष्य हासिल कर रही हैं। वे अपनी परंपरागत छवि का आवरण उतारकर नया इतिहास रच रही हैं। भारत में नारी शक्ति से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर वित्त वर्ष 2022-2023 में बढ़कर 37 प्रतिशत पर पहुंच गई है। 2021-2022 में यह दर 32.8 प्रतिशत रही थी। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 बताती है कि इस मामले में भारत ने आठ अंकों का सुधार किया है। इस समय लगभग दस हजार महिला अधिकारी देश की तीनों सेनाओं में कार्यरत हैं। हाल में चंद्रयान-3 की सफलता के पीछे भी अनेक महिला विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आज निजी क्षेत्र की 500 सबसे मजबूत तकनीकी कंपनियों में 11.6 लाख महिलाएं अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

इस सबके बावजूद अभी भी महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए सरकार के साथ-साथ समाज को भी अपनी पुरुषवादी सोच से आगे बढ़कर कार्य करना होगा। सवाल है कि महिला सशक्तीकरण के लिए देश एवं प्रदेशों के स्तर से किए जा रहे सघन प्रयासों के बाद भी वह कौन सी प्रवृत्ति है, जो लोगों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने को उकसाती है? इस संदर्भ में परिवार का समाजशास्त्र बताता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक प्रकार की प्रवृत्ति है, जो हिंसा-प्रवृत्त व्यक्तित्व में समाहित रहती है। ऐसे लोग शक्की मिजाज, वासनामय, विवेकहीन, व्यभिचारी, भावनात्मक रूप से अशांत और ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। हिंसा करने वाले व्यक्ति में ये लक्षण उसके प्रारंभिक जीवन में विकसित होते हैं। ऐसे हिंसा-प्रवृत्त लोग अपने जीवन की हताशा के कारण महिलाओं पर वर्चस्व कायम करने के लिए अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। लिहाजा इस कड़ी को कमजोर करने के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानूनों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना होगा। बच्चों के एकाकीपन को दूर करने के लिए परिवारों को संवाद की परंपरा बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को प्रेम और स्नेह का आवरण भी प्रदान करना होगा। सरकारों को भी समग्र रूप में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी संस्थाओं को साथ लेकर इनसे जुड़े कानूनों की जानकारी तथा इन्हीं से जुड़ी योजनाओं में भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 में जिस विकसित भारत का खाका खींचा है, उसका रास्ता आधी आबादी की पूर्ण सुरक्षा और बहुआयामी विकास से होकर ही निकलेगा। इसलिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक सघन विमर्श की आवश्यकता है।

संपादकीय

क्यों महंगी खाने की थाली?

बेशक दूसरी तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था की विकास-दर 7.5 फीसदी से अधिक रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन का आकलन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 (31 मार्च तक) के वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी। यदि चार साल की औसत विकास-दर को देखें, तो वह 4.5 फीसदी के करीब है। विकास-दर के अपने-अपने दावे किए जाते रहेंगे, लेकिन देश के आम आदमी के खाने की थाली अब भी महंगी है और यह महंगाई बढने के आसार हैं। आटा 16 फीसदी, चावल करीब 15 फीसदी, चीनी करीब 11 फीसदी और तुअर दाल 16 फीसदी से अधिक महंगी हुई है। इन वस्तुओं के थोक के दाम जो भी हैं, लेकिन खुदरा बाजार में मनमानी चल रही है। दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। यह देश की अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाली एजेंसी 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी' (सीएमआईई) एवं कुछ सरकारी एजेंसियों की ताजा रपट के निष्कर्ष हैं।

आने वाले तीन माह के दौरान भी इन खाद्यान्नों के दाम 14.55 फीसदी बढ़ सकते हैं। बीते 6 महीने के दौरान आटा, दाल, चावल और चीनी के दाम औसतन 14 फीसदी बढ़े हैं। सत्ता के पैरोकारों की दलील रही है कि देश के 81 करोड़ से ज्यादा गरीबों को तो 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत मुफ्त 5 किलो माहवार अनाज मुहैया कराया जाता है, लिहाजा खाद्यान्न के प्रति आम आदमी निश्चिंत हो सकता है। ऐसे में आम आदमी अपनी आमदनी को किसी और वस्तु तथा सेवा में खर्च कर सकता है। सरकारी पैरोकारों ने ये दलीलें 13.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालने के संदर्भ में दी हैं। गरीबी का मुद्दा तो आज भी विवादास्पद है, क्योंकि ऐसा आकलन करने वाले बौद्धिक, सामाजिक वर्ग के जिम्मेदार लोग हैं, जो आज भी 23.5 करोड़ भारतीयों को 'गरीबी-रेखा' के तले मानते हैं, क्योंकि वे गरीब 375 रुपए रोजाना कमाने में भी असमर्थ हैं। बहरहाल इस मुद्दे का विश्लेषण फिर कभी किया जा सकता है, लेकिन गरीबी और खाद्यान्न की लगातार महंगाई के आपसी गहरे संबंध हैं। यह सवाल बार-बार पूछा जाता रहा है कि अर्थव्यवस्था के विकास के बावजूद आम खाने की थाली महंगी क्यों होती रहती है? फिलहाल महंगे दामों के बुनियादी कारण कमजोर मानसून, किसानों का दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट होना और ज्यादा गर्मी से उत्पादन प्रभावित माने जा रहे हैं। क्या हम आज भी मौसम पर आधारित कृषि के भरोसे हैं? कृषि की विकास-दर घटकर 1 फीसदी से कुछ ज्यादा तक क्यों लुढक़ आई है? कोरोना-काल में भी कृषि की विकास-दर 3 फीसदी से अधिक रही थी। केंद्र सरकार ने दामों को नियंत्रित करने के मद्देनजर साल भर अपने भंडारों से गेहूं निकाल कर खुले बाजार में बेचा है।

नतीजतन गेहूं के भंडारण 2.39 करोड़ टन ही बचे हैं। यह बीते साल के 3.77 करोड़ टन से कम है। यानी सरकारी भंडारों में गेहूं करीब 37 फीसदी कम हो गया है। यह भी आकलन किया गया है कि भारत सरकार रूस से, पहले चरण में, 10 लाख टन गेहूं का आयात कर सकती है। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान का देश रहा है। फिर भी गेहूं की कमी का मुद्दा सवालिया है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, चावल, दाल, गन्ना आदि का उत्पादन भी, बीते सालों की तुलना में, कम रहा है। क्या भारत किसी संभावित खाद्य-संकट की ओर बढ़ रहा है? सीएमआईई की रपट के मुताबिक, गन्ने की फसल से 3.32 करोड़ टन इस बार एथेनॉल में शिफ्ट होने के कारण चीनी के दाम बढ़ेंगे। महंगे दामों का असर किसी भी चुनाव पर देखने में नहीं आया है।

कौन अच्छा, कौन बुरा ?

ये बात महाभारत के समय की है, पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोणाचर्य शिक्षा दे रहे थे।

एक बार उनके मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया।

उन्होंने अपने शिष्य दुर्योधन को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहा –वत्स एक काम करो, किसी अच्छे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ।

दुर्योधन ने कहा– ठीक है आचार्य, मैं अभी ही आश्रम से निकल जाता हूं और अच्छे आदमी की खोज शुरु करता हूं।

दुर्योधन कुछ दिनों बाद वापस आश्रम लौटकर आया और आचार्य को बताया– आचार्य मैंने पूरे ध्यान से हर जगह जाकर दूर–दूर तक खोजा लेकिन मुझे एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला जिसे मैं आपके पास ला सकता।

इस पर आचार्य ने कहा–ठीक है तुम युधिष्ठिर को मेरे पास भेज दो।

युधिष्ठिर जब आचार्य के पास आया तो उन्होंने उसे कहा– वत्स एक काम करो, किसी बुरे आदमी की खोज करो और उसे मेरे पास लेकर आओ। युधिष्ठिर ने हामी भरी और अब वो खोज के लिए निकल पड़ा।

कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर भी बिना किसी को अपने साथ लाए आश्रम लौट आया।

आचार्य ने उससे पूछा– वत्स तुमने कई शहरों का इतने दिनों तक भ्रमण किया और फिर भी तुम एक भी बुरे आदमी को लेकर नहीं आ पाए।

युधिष्ठिर ने जवाब दिया–जी गुरुजी, मुझे किसी भी आदमी में इतनी ज़्यादा बुराई नहीं दिखी कि उसे सबसे बुरा मानकर आपके पास ला पाता।

इस पर बाकी सारे शिष्य बड़े हैरान हुए और आचार्य से बोले– गुरुजी ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला!

तब गुरुजी ने समझाया– शिष्यों जब हम किसी के बारे में देखते है तो उसे उस नजर में देखते है जैसे हम खुद होते है। फिर हम उस नज़रिये से ही किसी को परखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या बुरा।

युधिष्ठिर को कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया क्योंकि वो स्वयं अच्छा है तो उसे बाकी सब भी अच्छे लगे और कोई बुरा नहीं लगा।

शिष्यों केवल अपने–अपने नजरियें का फर्क है। तुम जिस व्यक्ति में जो देखना चाहते हो तुम्हें वही दिखेगा।

किसी का अच्छा या बुरा होना केवल उसके स्वभाव पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं करता है, हमारी सोच और नजरिये पर भी निर्भर करता है। किसी को परखने में हमारे खुद के नजरिये का भी बहुत महत्व होता है

अकेलापन महसूस करने में शर्मिंदगी कैसी, मिलने–जुलने से खुलेंगे संबंधों के बंद द्वार

मन: प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते।।

अर्थात् मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिन्तन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करना, मन सम्बन्धी तप कहा जाता है।

भीष्म पर्व, गीता 17/16
(अर्जुन के प्रति साक्षात् भगवान श्रीकृष्ण का गीतोपदेश)

आज के युवा मोबाइल की छोटी-सी स्क्रीन पर जिसे कनेक्शन मानते हैं, उसका लोगों से कनेक्ट होने से कोई लेना-देना नहीं होता। महज सोशल मीडिया पर लाइक करने या मैसेज भेज देने भर से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो जाते। इसके बजाय आपको लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे संबंधों के बंद द्वार फिर से खुल सकते हैं।

छप्पन साल की रेनेट बेलो इस क्रिसमस पर अपने पड़ोसी के कुत्तों की देखभाल करते हुए अकेले ही छुट्टियां बिताएंगी। वह मानती हैं कि जिंदगी में उन्हें संतुलन खोजने की जरूरत है। सर्जन और टुगेदर- द हीलिंग पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन ए समटाइम्स लोनली वर्ल्ड के लेखक डॉ विवेक एच मूर्ति कहते हैं कि अकेलापन शर्मिंदगी की वजह बन सकता है और इससे आत्मसम्मान की भावना में भी कमी आ सकती है। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि अकेलापन एक मौलिक मानवीय अनुभव है। उनके अनुसार जैसे हम भूख व प्यास का अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही सभी कभी–कभी अकेलेपन का भी अनुभव करते हैं। समाज में जो संबंध हम बनाते हैं, वे जब टूटते हैं, तो पूरे शरीर पर असर डालते हैं।

एक सर्वे के मुताबिक आज आधे से ज्यादा अमेरिकी अकेलेपन के शिकार हैं। 400 फ्रैंड्स एंड नो वन टु कॉल के लेखक 69 साल के वाल वॉकर अपना एक सामाजिक नेटवर्क तैयार करने के लिए काफी मेहनत की। लेकिन उन्हें अकेलेपन का एहसास तब हुआ, जब जरूरत होने पर भी उनका साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। संबंधों से जो आपकी अपेक्षा है, वह अगर पूरी न हो रही हो, तो भी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं।

डॉ मूर्ति के अनुसार संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको लगातार कोशिश करते रहनी होती है और ईमानदारी भी बरतनी होती है। आज के युवा मोबाइल की छोटी–सी स्क्रीन पर जिसे कनेक्शन मानते हैं, उसका लोगों से कनेक्ट होने से कोई लेना–देना नहीं होता। महज सोशल मीडिया पर लाइक करने या मैसेज भेज देने भर से आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो जाते। इसके बजाय आपको लोगों से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे संबंधों के बंद द्वार फिर से खुल सकते हैं।

शिकागो यूनिवर्सिटी के शोध वैज्ञानिक लुइस हॉकले के अनुसार अगर आप किताबी कीड़े हैं, तो आप यह न सोचें लोग आपके दोस्त बनना पसंद करेंगे। साझा मूल्य व साझा हित ही दोस्ती की नींव रखते हैं। रिश्ते बनने में समय लगता है, शुरुआत में ही ज्यादा अपेक्षाएं न रखें। सामाजिक नेटवर्क को व्यापक बनाने का एक तरीका स्वयंसेवा भी है।

ब्रिटेन में दस हजार स्वयंसेवकों पर किए गए एक अध्ययन में करीब दो–तिहाई स्वयंसेवक इस बात पर सहमत थे कि स्वयंसेवा से उन्हें कम अलग–थलग महसूस होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करने से आपको खुलने का मौका मिलेगा। लोगो को तौलते रहने के बजाय, उन्हें समझने की कोशिश आपको ज्यादा लोकप्रिय बनाएगी। डॉ हॉकले के अनुसार, अकेलेपन से ग्रस्त लोगों का खुद पर जितना वह सोचते हैं, उससे ज्यादा नियंत्रण होता है।

चिकित्सा के पवित्र पेशे का यह हश्र... कभी सोचा नहीं था

तस्लीमम नसरीन

भारतीय डॉक्टरों की पेशेवर दक्षता पर मुझे इतना विश्वास है कि बांग्लादेश में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मेरे दोस्तों–रिश्तेदारों को भारत आकर इलाज कराने के लिए कहती हूं। मेरे जो परिचित दूसरे देशों में हैं, उनसे भी कहती हूं कि शरीर की जांच या बीमारी के इलाज की अगर जरूरत पड़े, तो अस्पतालों में भारतीय चिकित्सकों को तरजीह दें। मैं भी जब अमेरिका जाती हूं, और चिकित्सीय जांच की जरूरत पड़ती है, तब अस्पतालों में पता करती हूं कि भारतीय डॉक्टर हैं या नहीं। अगर भारतीय डॉक्टर होते हैं, तो श्वेत अमेरिकियों को दरकिनार कर भारतीय डॉक्टर से सलाह लेती हूं। भारत से बाहर भारतीय चिकित्सकों पर मुझे इतना भरोसा क्यों है? इसका कारण क्या यह है कि हमारा इतिहास एक है? इसकी वजह क्या यह है कि एक ही उपमहाद्वीप का हिस्सा होने के कारण हम निकटता महसूस करते हैं?

ये सब कारण तो हैं ही, लेकिन असल कारण यह है कि पेशेवर दक्षता की कसौटी पर भारतीय डॉक्टर दूसरे देशों के डॉक्टरों से बहुत आगे हैं। भारतीय युवा मुश्किल प्रतियोगिताओं में बैठकर और पास होकर मेडिकल में दाखिला लेते हैं, फिर कठिन परीक्षा पास कर डॉक्टर बनते हैं। भारत से बाहर विकसित देशों तक में भारतीय डॉक्टर इतने सफल हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पेशेवर दक्षता ही है। यह अलग बात है कि पिछले साल के एक भीषण व्यक्तिगत अनुभव के बाद मेरी यह धारणा कुछ हद तक खंडित हुई है कि सभी भारतीय चिकित्सक अच्छे और अपने पेशे के प्रति ईमानदार ही होते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी की खबरें बीच–बीच में आती रहती हैं।

कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल के एक विख्यात हृदयरोग विशेषज्ञ को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने कुल छह सौ मरीजों के शरीर में नकली और खराब पेसमेकर लगाए थे। पता यह चला कि जिन लोगों को पेसमेकर की जरूरत नहीं थी, उनके शरीर में भी जबरन पेसमेकर लगाए गए थे। इनमें से अनेक लोगों की या तो मृत्यु हो गई, या फिर वे शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया भला? क्योंकि उन्हें टारगेट पूरा करना था। जाहिर है, ऐसा उन्होंने पैसा कमाने के लिए ही किया।

एक आंकड़ा बताता है कि भारत में 44 फीसदी ऑपरेशन गैरजरूरी होते हैं। यानी जहां सर्जरी की जरूरत नहीं है, वहां भी सर्जरी की जाती है। भारत में दिल के 55 फीसदी, गर्भाशय के 48 प्रतिशत, कैंसर के 47 प्रतिशत, घुटना प्रत्यारोपण के 48 फीसदी और 47 प्रतिशत सिजेरियन ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। अस्पतालों का कॉरपोरेटीकरण हो चुका है, इसी कारण बड़ी संख्या में सर्जरी की जरूरत है। ज्यादातर अस्पताल अब लोगों के स्वास्थ्य और मरीजों की सेवा के लिए नहीं हैं। खासकर अधिकतर निजी अस्पताल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हैं।

एक आंकड़ा बताता है कि भारत में 44 फीसदी ऑपरेशन गैरजरूरी होते हैं। यानी जहां सर्जरी की जरूरत नहीं है, वहां भी सर्जरी की जाती है। भारत में दिल के 55 फीसदी, गर्भाशय के 48 प्रतिशत, कैंसर के 47 प्रतिशत, घुटना प्रत्यारोपण के 48 फीसदी और 47 प्रतिशत सिजेरियन ऑपरेशन ऐसे ही होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। अस्पतालों का कॉरपोरेटीकरण हो चुका है, इसी कारण बड़ी संख्या में सर्जरी की जरूरत है। ज्यादातर अस्पताल अब लोगों के स्वास्थ्य और मरीजों की सेवा के लिए नहीं हैं। खासकर अधिकतर निजी अस्पताल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में जितने डॉक्टर और नर्स हैं, उनसे भी ज्यादा वहां अस्पतालों का मुनाफा बढ़ाने वाले लोग होते हैं। सर्जनों को वहां मोटा वेतन अमूमन दिया ही इसलिए जाता है कि वे बड़ी संख्या में सर्जरी करेंगे और अस्पतालों की आमदनी बढ़ाएंगे।

मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसलिए डॉक्टरों को सेवा का उद्देश्य भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागते देखना मुझे दुखद लगता है। मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले नए डॉक्टरों को अपने पेशे के प्रति ईमानदार बने रहने की शपथ लेनी पड़ती है। इसे हिपोक्रेटिज की शपथ कहते हैं। प्राचीन यूनान के चिकित्सक हिपोक्रेटिज के नाम पर इस शपथ की शुरुआत ईसा पूर्व पांचवीं सदी में हुई थी। यह शपथ इस तरह है – *किसी मरीज का नुकसान नहीं करूंगा। रोगी की बेहतरी के लिए तमाम उपाय अपनाऊंगा। दूसरे चिकित्सकों को अपना परिवार समझूंगा और नि:स्वार्थ भाव से उनकी चिकित्सा और सेवा करूंगा।*

घुटने पर चोट लगने के कारण जिस दिन मैं नई दिल्ली स्थित एक बड़े और नामचीन निजी अस्पताल में गई थी, उस दिन चिकित्सक के साथ मैं एक मरीज भी थी। लेकिन उस अस्पताल के डॉक्टर ने सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए, केवल पैसे के लिए मेरा हिप जॉयंट काटकर अलग कर, उसकी जगह घटिया इम्प्लांट लगाकर मुझे बर्बाद कर दिया। डॉक्टर होते हुए भी उस दिन वह हिपोक्रेटिज की शपथ भूल गए थे। सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि रोज अपने पेशे में लगे डॉक्टर कितनी बार हिपोक्रेटिज की शपथ भूलते होंगे। मानो अपने मुनाफे के लिए गैरजरूरी सर्जरी कर देना ही कम बड़ा अपराध न हो, अपना झूठ छिपाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मुझे झूठी रिपोर्ट सौंपकर और भी बड़ा अपराध किया। चूंकि मैं डॉक्टर रह चुकी हूं, इसलिए उनका झूठ पकड़ पाने में सफल हुई। जबकि रोज असंख्य लोग चिकित्सा की दुनिया में व्याप्त इस फर्जीवाड़े का शिकार होते होंगे।

उस व्यक्तिगत त्रासदी के आठ महीने से ज्यादा हो गए, आज भी मेरे लिए वह दुस्वप्न सरीखा है। मैं पहले की तरह स्वस्थ और स्वाभाविक जीवन में नहीं लौट पाई। मैं वर्कआउट नहीं कर पाती। ऐसे में, कितने दिन स्वस्थ रह पाऊंगी, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में मुझमें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की जटिलताएं बढ़ जाएंगी। जिस भी दिन यह इम्प्लांट टूट जाएगा, उस दिन व्हील चेयर के अलावा मेरे पास चलने का कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा।

चिकित्सा के क्षेत्र में व्याप्त यह दुष्प्रवृत्ति हालांकि पहले भी मुझे चिंतित, विचलित करती थी। पर व्यक्तिगत अनुभव के बाद मेरी चिंता कहीं और बढ़ गई है, जिसमें मेरे अपने जीवन की चिंता भी शामिल है।

कुछेक डॉक्टरों की कारस्तानियों को देखते हुए अब चिकित्सकों पर मेरा भरोसा पहले की तरह नहीं रहा। कॉरपोरेट संस्कृति ने चिकित्सा के पवित्र पेशे को जैसे मुनाफे के व्यापार में बदल दिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब मरीजों की मृत्यु हो जाने के बावजूद उनके परिजनों से ज्यादा पैसे लेने के लिए शव को वेंटिलेटर से नहीं हटाया जाता। ऐसे भी उदाहरण हैं, जब पैसा न होने पर शवों को अस्पतालों से नहीं ले जाने दिया जाता। डॉक्टर पिता के सान्निध्य में बड़े होते हुए मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस पेशे का यह हश्र होगा।

खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ आहार की लागत और पोषण के लिए विविधता की जरूरत

पत्रलेखा चटर्जी

दुनिया जिन विविध संकटों का सामना कर रही है, उनमें पर्यावरणीय, सामाजिक, तकनीकी एवं आर्थिक संकट प्रमुख हैं। इनका संयुक्त प्रभाव भविष्य में अधिक तीव्रता के साथ अप्रत्याशित झटकों का कारण बन सकता है। ऐसे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत उच्च विकास दर और मध्यम दर्जे की मुद्रास्फीति के साथ नए वर्ष 2024 में प्रवेश कर रहा है।

मगर आशावादियों को भी मानना होगा कि भारत बेशक प्रगति की राह पर अग्रसर है, पर आम लोगों को अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना होगा। हमारे भविष्य की तस्वीर इसी बात पर निर्भर करेगी कि हम किन चीजों पर बात करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं।

हाल के दशकों में भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश के एक बड़े वर्ग को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, तो कई सवाल खड़े होते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा भोजन है। हम आज जो खाते हैं, वह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि शहरी भारत में बढ़ते मोटापे और इसके परिणामस्वरूप जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को काफी महत्व दिया जाता है, पर सच्चाई यह है कि कुल मिलाकर हम अल्पपोषित लोगों का देश हैं। इस अल्पपोषण का प्रभाव स्वास्थ्य एवं पोषण से परे आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा एशिया ऐंड पैसिफिक–रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी ऐंड न्यूट्रीशन, 2023 शीर्षक से जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि भोजन, चारा और ईंधन की कीमतों और वैश्विक महामारी से उबरने की धीमी गति ने एशिया–प्रशांत क्षेत्र में पहले से ही कमजोर लाखों लोगों के स्वास्थ्य एवं आजीविका को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।

एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में दक्षिण एशिया में ऐसे लोगों की संख्या सर्वाधिक (1.4 अरब) थी, जो स्वस्थ आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। भारत में वर्ष 2020 में 76.2 फीसदी लोग स्वस्थ भोजन का खर्च उठाने में असमर्थ थे। हालांकि 2021 में स्थिति थोड़ी सुधरी, लेकिन तब भी 74.1 फीसदी भारतीय स्वस्थ एवं पोषक आहार पाने में असमर्थ थे।

अगर हम एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें खुद को बेहतर देशों से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अपने से खराब या दक्षिण एशिया के अन्य देशों से तुलना करनी चाहिए। हम पद्धतियों और परिभाषाओं पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते कि हर भारतीय को स्वस्थ आहार उपलब्ध कराने के लिए हमें जमीनी स्तर पर बहुत काम करना होगा, जब तक हम अपने भविष्य को कमजोर करते रहेंगे।

मोदी सरकार द्वारा चलाई गई मुफ्त राशन योजना 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की मदद कर रही है। इसने बहुत से लोगों को भुखमरी और अकाल से दूर किया है। लेकिन बच्चों और वयस्कों को बढ़ने और विकास करने के लिए आहार में विविधता की जरूरत होती है। उन्हें प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।

कटु सच्चाई यह है कि अधिकांश भारतीय (चाहे वे शाकाहारी हों या मांसाहारी) स्वस्थ आहार नहीं लेते हैं, क्योंकि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। कितने भारतीय पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से फल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे आदि खरीद सकते हैं?

भारत आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, लेकिन उस विकास का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। लाखों लोग खाद्य–असुरक्षा का सामना करते हैं, क्योंकि वे उतना कमा नहीं पाते कि घर के सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ आहार का खर्च वहन कर सकें। बेशक यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि कई देशों के लिए सच है। चाहे कोई भी पार्टी चुनाव में जीतकर सत्ता में आए, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

यह देश के प्रत्येक राज्य के लिए स्वागत योग्य कदम होगा कि वे स्वस्थ आहार की लागत का पता लगाएं और फिर स्वस्थ आहार के विकल्पों को सुलभ एवं किफायती बनाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर पहल करें। किफायती स्वस्थ आहार के बारे में व्यापक जन जागरूकता भी जरूरी है।

क्या कानून में बदलावों से महफूज होगी 'नारी'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन बिल प्रस्तुत किए हैं। इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लोकसभा और राज्यसभा ने इन बिलों को पास कर दिया है। शाह का मानना है कि ये बिल सिर्फ संशोधन बिल नहीं हैं, इनकी मदद से पूरा कानून ही बदल जाएगा...

देश में अपराध के पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें, तो महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। साल 2013 में महिलाओं के खिलाफ हुए ऐसे अपराध, जिनमें आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे, वह संख्या 2,95,896 थी। साल 2022 में अगर इस संख्या को देखें, तो वह 3,65,300 पर पहुंच गई है। रोजाना औसतन एक हजार महिलाओं के खिलाफ आईपीसी में आने वाले अपराध हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन बिल प्रस्तुत किए हैं। इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लोकसभा और राज्यसभा ने इन बिलों को पास कर दिया है। शाह का मानना है कि ये बिल सिर्फ संशोधन बिल नहीं हैं, इनकी मदद से पूरा कानून ही बदल जाएगा। ये बिल मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुनियादी बदलाव लाएंगे।

देश में अपराध के पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें, तो महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। साल 2013 में महिलाओं के खिलाफ हुए ऐसे अपराध, जिनमें आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे, वह संख्या 2,95,896 थी। साल 2022 में अगर इस संख्या को देखें, तो वह 3,65,300 पर पहुंच गई है। रोजाना औसतन एक हजार महिलाओं के खिलाफ आईपीसी में आने वाले अपराध हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीन बिल प्रस्तुत किए हैं। इंडियन पीनल कोड 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लोकसभा और राज्यसभा ने इन बिलों को पास कर दिया है। शाह का मानना है कि ये बिल सिर्फ संशोधन बिल नहीं हैं, इनकी मदद से पूरा कानून ही बदल जाएगा। ये बिल मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुनियादी बदलाव लाएंगे।

नए बिलों में महिलाओं/बच्चों के अपराध को

महिलाओं के प्रति बढ़ रहे आईपीसी अपराध ...

साल	आईपीसी के तहत दर्ज मामले
2013	295896
2014	326115
2015	315632
2016	325652
2017	315215
2018	323304
2019	342639
2020	311354
2021	357671
2022	365300

लेकर क्या

- भारतीय न्याय संहिता ने यौन अपराधों से निपटने के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध' नामक एक नया अध्याय पेश किया है।
- इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है।
- नाबालिग बच्चियों के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बनाता है।
- 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है।
- गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान
- 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार का एक नई अपराध कैटेगरी।
- धोखे से यौन संबंध बनाने या विवाह करने के सच्चे इरादे के बिना विवाह करने का वादा करने वाले व्यक्तियों के लिए लक्षित दंड का प्रावधान करता है।
- e-FIR के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पेश करता है। संवेदनशील अपराधों की त्वरित रिपोर्टिंग में सहायता करता है।
- नए विधेयक उन संज्ञेय अपराधों के लिए e-FIR की भी अनुमति देते हैं, जहां आरोपी अज्ञात होता है।
- इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट करने के लिए एक विवेकशील अवसर प्रदान करता है।

भारतीय न्याय संहिता

- इसमें 358 धाराएं होंगी (IPC की 511 धाराओं के स्थान पर)
- 20 नए अपराधों को जोड़ा गया है
- 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ाया गया है
- 83 अपराधों में जुर्माने की सजा राशि को बढ़ाया गया है
- 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है
- 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरु किया गया है
- 19 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

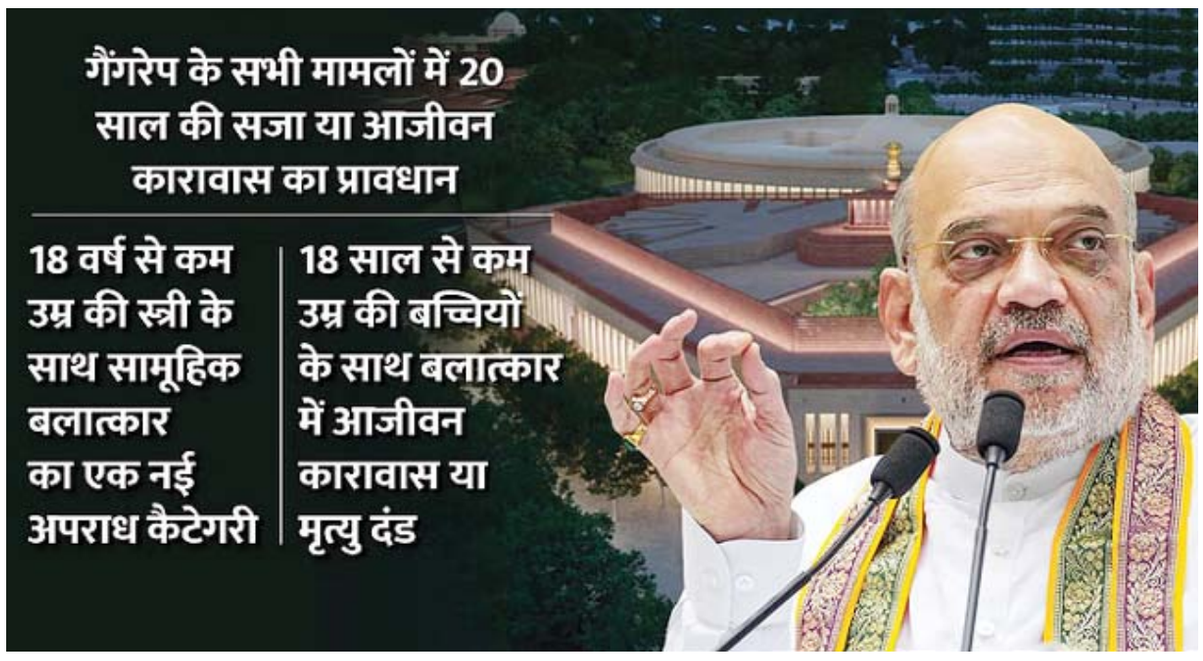

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

- इसमें 531 सेक्शन होंगे (ष्टह्वक्क की 484 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 177 प्रोविजन में बदलाव हुआ है,
- 9 नए सेक्शन, 39 नए सब-सेक्शन जोड़े गए हैं
- 44 नए प्रोविजन तथा स्पष्टीकरण जोड़े गए है
- 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई हैं ? 35 जगह पर ऑडियो-विडियो का प्रावधान जोड़ा गया है
- 14 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

- इसमें 170 धाराएं होंगी (मूल 167 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 24 धाराओं में बदलाव किया गया है
- 2 नई धारा, 6 उप-धाराएं जोड़ी गई हैं
- 6 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

भारतीय न्याय संहिता, प्रमुख विशेषताएं

भारतीय जरूरतों के अनुसार प्रायोरिटी

- ब्रिटिश शासन को मानव-वध या महिलाओं पर अत्याचार से महत्त्वपूर्ण राजद्रोह और खजाने की रक्षा थी
- इन तीन कानूनों में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों, हत्या और राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों को प्रमुखता दी गई है।
- इन कानूनों की प्रायोरिटी भारतीयों को न्याय देने का है, उनके मानवाधिकारों के रक्षा की है

आतंकवाद की टूटेगी कमर

- भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई है
- इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है।
- व्याख्या-भारतीय न्याय संहिता खंड 113. (1)- जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बमों, डाइनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, अपायकर गैसों, न्यूक्लीयर का उपयोग करके ऐसा कार्य करता है, जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, संपत्ति की हानि होता है, या करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन तो वह आतंकवादी कार्य करता है।
- आतंकी कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय है जिसमें पैरोल नहीं होगा;
- आतंकी अपराधों की एक श्रृंखला भी पेश की गई है।
- सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना अपराध है,
- ऐसे कृत्यों को भी इस खंड के तहत शामिल किया गया है जिनसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति या विनाश के कारण व्यापक हानि होती है।

संगठित अपराध (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम)

- संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई है।
- भारतीय न्याय संहिता 111. (1) में पहली बार संगठित अपराध की व्याख्या की गई है
- सिंडिकेट से की गई विधिविरुद्ध गतिविधि को दंडनीय बनाया है।
- नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां अथवा भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जोड़ा गया है।
- छोटे संगठित अपराधों को भी अपराध घोषित किया गया है, जिसके लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है। इससे संबंधित प्रावधान खंड 112 में हैं।
- आर्थिक अपराध की व्याख्या भी की गई है-करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टांपों का हेरफेर, कोई स्कीम चलाना या किसी बैंक/वित्तीय संस्था में गड़बड़ ऐसे कृत्य शामिल है;
- संगठित अपराध में, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो आरोपी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा
- जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा।
- संगठित अपराध में सहायता करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है।

विक्टिम-सेंट्रिक ...

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम-सेंट्रिक सुधार के 3 प्रमुख फीचर्स होते है-

1. पार्टिसिपेशन का अधिकार (विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका, BNSS 360)
2. इनफार्मेशन का अधिकार (BNSS खंड 173, 193 और 230)
3. नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार

और यह तीनों फीचर्स नए कानूनों में सुनिश्चित किये गए हैं

- जीरो स्न्ढ्ढक्र दर्ज करने की प्रथा को संस्थागत बना दिया गया है (BNSS 173)

FIR कहीं भी दर्ज कर सकते हैं, भले ही अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो।

विक्टिम के सूचना के अधिकार

- विक्टिम को FIR की एक प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने का अधिकार।
- विक्टिम को 90 दिनों के भीतर जांच में प्रगति के बारे में सूचित करना ।
- पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट, स्न्ढ्ढक्र गवाह के बयान आदि के अनिवार्य प्रावधान के माध्यम से उनके मुकदमे के ब्योरे की जानकारी का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
- जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों में पीड़ितों को जानकारी प्रदान करने के लिए उपबंध शामिल किए गए हैं।

भारतीय न्याय संहिता धारा 152

जो कोई, जानबूझकर या प्रयोजन पूर्वक, बोले गए या लिखे गए शब्दों से, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रमुख फीचर

टाइम-लाइन

- आपराधिक कार्यवाही शुरू करने, गिरफ्तारी, जांच, आरोप पत्र, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही, कॉग्निज़्स, चार्जेज, प्ली बारगेनिंग, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति, ट्रायल, जमानत, जजमेंट और सजा, दया याचिका आदि के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिससे स्पीडी डिलीवरी ऑफ़ जस्टिस संभव होगी।
- BNSS में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से शिकायत देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर स्न्ढ्ढक्र को रिकॉर्ड पर लिया जाना होगा।
- यौन उत्पीड़न के पीड़ित की चिकित्सा जांच रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनर द्वारा 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को फॉरवर्ड की जाएगी।
- पीड़ितों/मुखबिरों को जांच की स्थिति के बारे में सूचना 90 दिनों के भीतर दी जाएगी।
- आरोप तय करने का काम सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप की पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर किया जाना होगा।
- मुकदमे में तेजी लाने के लिए, अदालत द्वारा घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा शुरू करना आरोप तय होने से 90 दिनों के भीतर होगा।
- किसी भी आपराधिक न्यायालय में मुकदमे की समाप्ति के बाद निर्णय की घोषणा 45 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- सत्र न्यायालय द्वारा बरी करने या दोषसिद्धि का निर्णय बहस पूरी होने से 30 दिनों के भीतर होगा, जिसे लिखित में मेंशनड कारणों के लिए 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

120 दिन में आईएस-आईपीएस और दूसरे सिविल अफसरों पर मुकदमा चलाने की सहमति-असहमति देनी होगी

आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों बिलों को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है। नए कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं। नए कानूनों में आतंकवाद, महिला विरोधी अपराध, देश द्रोह और मॉब लिंचिंग से संबधित कई नए प्रावधान पेश किए गए हैं। इतना ही नहीं, देश में अगर कोई सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस/आईपीएस या अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आवश्यकता है, तो उस मामले में देरी नहीं होगी।

सक्षम अधिकारी या अथॉरिटी को इस मामले में मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। सिविल सर्वेंट्स के विरुद्ध प्रॉसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारी 120 दिनों के अंदर निर्णय लेगा। यदि ऐसा न हो, तो यह मान लिया जाएगा कि अनुमति प्रदान हो गई है। सिविल सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य उसका प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर टेस्टीमनी दे सकेगा।

जांच की प्रगति को लेकर शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाएगा। पारंपरिक प्रचलन से हटकर पुलिस के लिए सख्ती से 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के संबंध में शिकायतकर्ता को बताना जरूरी है। न्यायिक क्षेत्र में दो चीजों पर बल दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया, सुनवाई में तेजी लाना और अनुचित स्थगन पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। धारा 392(1) में 45 दिनों के भीतर निर्णय की बात करते हुए मुकदमे को खत्म करने के लिए बेहतर ढंग से एक समयसीमा निर्धारित की गई है। न्याय में विलंब का अर्थ न्याय से वंचित होना है।

टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रक्रिया बनाई जाएगी। क्राइम सीन से इन्वेस्टीगेशन और ट्रायल तक, सभी चरणों में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। इसके माध्यम से पुलिस जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। सबूतों की गुणवत्ता में सुधार होगा। विक्टिम और आरोपियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी। यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट तथा जजमेंट तक सभी डिजिटाइज्ड हो जायेंगे। सभी पुलिस थानों और

न्यायालयों द्वारा एक रजिस्टर द्वारा ई-मेल एड्रेस, फोन नंबर अथवा ऐसा कोई अन्य विवरण रखा जाएगा। एविडेंस, तलाशी व जब्ती में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। इसे 'अविलंब' मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की आवश्यकता है। पुलिस जांच के दौरान दिए गए किसी भी बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प रहेगा। सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में %फोरेंसिक एक्सपर्ट% द्वारा क्राइम सीन पर फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन अनिवार्य होगा। वजह, इससे क्वॉलिटी ऑफ इन्वेस्टीगेशन में सुधार होगा। इन्वेस्टीगेशन साइंटिफिक पद्धति पर आधारित होगी और 100 फीसदी कन्विक्शन रेट का लक्ष्य पूरा होगा। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फॉरेंसिक के इस्तेमाल को जरूरी बनाया गया है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। इसके लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना पर फोकस किया गया है।

एनएफएसयू के कुल सात परिसर के अलावा 2 ट्रेनिंग अकादमी (गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, गुवाहाटी, भोपाल, धारवाड़) और सीएफएसएल पुणे एवं भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस अकादमी की शुरुआत की जा रही है। चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन किया गया है।

पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की पूरी प्रक्रिया अथवा किसी संपत्ति का अधिगृहण करने में इलेक्ट्रानिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफी होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मैजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी।

राज्य सरकार को एक पुलिस अधिकारी को नामित करने के लिए अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वह अधिकारी, सभी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी जानकारी को प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिला मुख्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना भी आवश्यक है। छोटे-मोटे मामलों में समरी ट्रायल द्वारा तेजी लाई जाएगी।

कम गंभीर मामलों, चोरी, चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना अथवा रखना, घर में अनधिकृत प्रवेश, शांति भंग करने, आपराधिक धमकी आदि जैसे मामलों, के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य बनाया गया है। उन मामलों में जहां सजा 3 वर्ष (पूर्व में 2 वर्ष) तक है, मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज कारणों के अंतर्गत ऐसे मामलों में समरी ट्रायल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और वह एक तिहाई कारावास काट चुका है, तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जहां विचाराधीन कैदी %आधी या एक तिहाई अवधि% पूरी कर लेता है, वहां जेल अधीक्षक अदालत को तुरंत लिखित में आवेदन दे। विचाराधीन कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सजा में रिहाई उपलब्ध नहीं होगी।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन, इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेज, वेबसाइट व लोकेशनल साक्ष्य। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड %दस्तावेज% की परिभाषा में शामिल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान %साक्ष्य% की परिभाषा में शामिल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानने के लिए और अधिक मानक जोड़े गए हैं। इसके माध्यम से उचित कस्टडी-स्टोरेज-ट्रांसमिशन-ब्रॉडकास्ट पर जोर दिया गया है। दस्तावेजों की जांच करने के लिए मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति एवं एक कुशल व्यक्ति के साक्ष्य को शामिल करने के लिए और अधिक प्रकार के माध्यमिक साक्ष्य जोड़े गए हैं। ये ऐसे साक्ष्य हैं, जिनकी जांच अदालत द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती है।

साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी स्वीकार्यता, वैधता और प्रवर्तनीयता स्थापित की गई। राज्य सरकार, एक एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करेगी और उसे नोटिफाईड भी करेगी। 10 वर्ष अथवा अधिक की सजा अथवा आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा वाले मामलों में दोषी को घोषित अपराधी (प्रोक्लेम्डल ऑफेंडर) घोषित किया जा सकता है। घोषित अपराधियों के मामलों में, भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान किया गया है। पहले केवल 19 अपराधों में ही प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित हो सकते थे, अब इसमें 120 अपराधों को इस दायरे में लाया गया है। इसमें बलात्कार के अपराध को भी शामिल किया गया है, जो पहले शामिल नहीं था।

न्यायपालिका, बोझ है कि घटता नहीं, तत्काल सुधार जरूरी

वैसे तो न्याय सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक अनिवार्य गुण है, पर भारत में इसका महत्व समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों से कहीं अधिक है। इसका कारण यह है कि भारत के संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवादी सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाया गया है। इस बारे में ऐसा कहना बेहतर होगा कि भारत में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए वितरण न्याय को सबसे महत्वपूर्ण उपकरण बनाया गया है। संसाधनों का आवश्यकतानुसार वितरण भारत का सांविधानिक लक्ष्य है। संविधान की उद्देशिका में न्याय का जो उल्लेख है, उससे यही सिद्ध होता है कि सामाजिक-आर्थिक न्याय दिए बिना राजनीतिक न्याय (अधिकारों की रक्षा) का कोई औचित्य नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि न्याय की मंशा क्या हो? इस बारे में ऐसा कहना समीचीन होगा कि हालांकि न्याय सदैव निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर यह विलंबित हो, तो जमीनी स्तर पर अर्थहीन हो जाएगा। न्याय में विलंब का एक बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कारण अदालतों में लंबित मामलों का बढ़ता बोझ है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, बीते जुलाई तक देश भर के विभिन्न न्यायालयों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से 85 प्रतिशत से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित थे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुसार, 14 जुलाई तक उच्च न्यायालयों में 60.62 लाख मामले लंबित थे और अधीनस्थ न्यायालयों में 4.41 करोड़ मामले लंबित थे। इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, एक जुलाई तक उच्चतम न्यायालय में 69,766 मामले लंबित थे।

हालांकि हाल ही में भारत के प्रधान न्यायमूर्ति ने मामलों के निपटारे के प्रति उच्चतम न्यायालय के दायित्व का हवाला देते हुए यह कहा है कि गत वर्ष देश के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 50 हजार मामलों का निपटारा किया और लगभग इतने ही मामले दर्ज किए गए। यानी गत वर्ष सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में इज़ाफा नहीं हुआ। प्रधान न्यायमूर्ति ने यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक समय में एक से अधिक सांविधानिक पीठ बनाई गई, ताकि बड़ी संख्या में लंबित सांविधानिक मामलों का निपटारा किया जा सके।

रिजर्व बैंक की राज्यों को चेतावनी, कहा

ना करें पुरानी पेंशन स्कीम के वादे, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा खर्च

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचें। इससे उनका खर्च कई गुना बढ़कर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी।

कुछ राज्यों में लागू हुई ओपीएस कुछ में चल रहा विचार

हाल ही में कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। साथ ही कर्नाटक में भी ओपीएस लाने की चर्चा चल रही है। आरबीआई ने राज्यों को सलाह दी है कि वह न्यू पेंशन स्कीम (ओपीएस) को ही जारी रखें। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस – अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2023-24 को जारी करते हुए चेताया कि अगर सारे राज्य ओपीएस फिर से लाते हैं तो उन पर वित्तीय दबाव लगभग 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। ओपीएस का जीडीपी पर बुरा असर दिखेगा। इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ 2060 तक जीडीपी का 0.9 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

विकास कार्यों के लिए नहीं होगा पैसा

आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, ओपीएस बहाल कर चुके राज्यों की तर्ज पर अन्य राज्य भी इसे लाने पर विचार करने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और विकास कार्यों पर खर्च में कमी आएगी। आरबीआई ने कहा कि ओपीएस पीछे जाने वाला कदम है। इससे पिछले सुधारों से मिला फायदा खत्म हो जाएगा। इससे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओपीएस का आखिरी बैच 2040 के शुरुआत में रिटायर होगा और उन्हें 2060 तक पेंशन मिलती रहेगी।

राजस्व बढ़ाएं, लोक लुभावन वादे न करें: आरबीआई

अगले साल देश में आम चुनाव हैं। ऐसे में आरबीआई ने लोक लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने के बजाय राजस्व में इजाफा करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्य अपनी कमाई में इजाफा करने के बारे में सोचें। राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस, स्टांप ड्यूटी, अवैध खनन रोकने, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी, एक्साइज और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करने पर ध्यान देना चाहिए जिससे उनका राजस्व बढ़ेगा।

भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा: शाह

देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत 2025 के अंत तक 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने यहां उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत पिछले एक दशक में हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा है। शाह ने कहा, दुनिया आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। 2014 से 2023 के बीच भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से उठकर पांचवीं (सबसे बड़ी) अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल के दौरान देश ने पहले कभी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई। उन्होंने इसका श्रेय मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की उनकी क्षमता को दिया।

शाह ने कहा कि मोदी जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वह आतंकवाद मुक्त दुनिया के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान की अगुवाई करने के अलावा अपने 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिये दुनिया की धीमी होती जीडीपी को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी-20 दिल्ली घोषणापत्र कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसे दुनिया आने वाले दशकों तक याद रखेगी। शाह ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है और इस दौरान देशभर में साढ़े 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

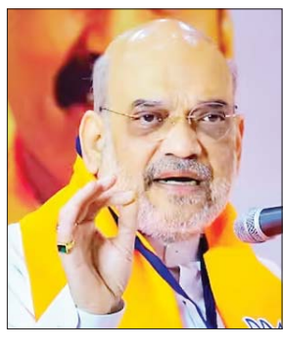

उन्होंने कहा, आईएमएफ ने भारत को अंधेरे में एक उज्ज्वल स्थान बताया है। मॉर्गन स्टेनली (वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म) ने कहा कि 2027 तक, भारत जापान और जर्मनी से आगे निकलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये अच्छे संकेत हैं। भारत का समय आ गया है।%% उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बताया कि उन्होंने सम्मेलन के लिए दो लाख करोड़ रुपये का निवेश लाने का लक्ष्य रखा है, तो उन्हें लगा कि यह असंभव है। शाह ने कहा, लेकिन मैं उन्हें पहले ही विभिन्न कंपनियों के साथ तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए बधाई देता हूं। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन उत्तराखंड के लिए कई नई चीजों की शुरुआत का प्रतीक है।%% उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बनने के दो दशकों के बाद वह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राज्य को अटल जी (पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी) ने बनाया था और अब मोदी जी इसका निर्माण कर रहे हैं।

शाह ने कहा कि उत्तराखंड दिल्ली के नजदीक स्थित देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ शनिवार को यहां परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में भाग लिया। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने दोनों मंत्रियों का उस समय स्वागत किया जब वे गंगा मैया की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम पहुंचे।

केंद्र ने जमाखोरी व बेईमान सट्टेबाजी को रोकने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए स्टॉक सीमा को ज्यादा कठोर कर दिया है पत्रकारों को जानकारी देते हुए खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए स्टॉक रखने के नियमों को तत्काल प्रभाव से और सख्त कर दिए गए हैं।

साथ ही उन्होंने बताया कि थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा मौजूदा 2000 टन से घटाकर 1 हजार टन कर दी गई है। वहीं प्रत्येक रिटेलर पर स्टॉक सीमा 10 टन से बजाए पांच टन, बड़े चेन रिटेलर के प्रत्येक डिपो के लिए 5 टन और सभी टिपो के लिए कुल एक हजार टन होगी। उन्होंने कहा कि प्रोसेसर के मामले में वे मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके रख सकते हैं।

खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि कमी को रोकने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा किया गया है। यह संशोधिक स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को स्टॉक को संशोधित सीमा तक कम करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। साथ ही हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करनी होगी। यदि कोई भी संस्था, जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 12 जून को खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के व्यापारियों पर मार्च 2024 तक स्टॉक रखने की सीमा लगा दी थी।

जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल-डीजल, सरकार की तैयारी

नई दिल्ली। देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती है। दरअसल, पिछले 20 महीनों से तेल की कीतमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब जो रिपोर्ट सामने आ रहा है। इससे लग रहा है कि जल्द ही देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार लोकसभा चुनाव से पहले वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की योजना पर विचार कर रही है। साल 2022 में पेट्रोल पर 17 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर के नुकसान के बाद अब ओमसी पेट्रोल पर 8-10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3-4 रुपये प्रति लीटर का प्रॉफिट कमा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोलियम मंत्रालय पहले ही ओएमसी के साथ कच्चे तेल और रिटेल प्राइस को लेकर चर्चा कर चुका है।

रिपोर्ट में आगे बताया या हा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (ह्रस्ष्ट) अब मुनाफा कमा रही हैं। इसलिए सरकार ने लोगों को कुछ राहत देने के लिए इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय मौजूदा कच्चे तेल की कीमत पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएमसी प्रोफिटेबिलिटी के अलावा, वे ग्लोबल फैक्टर्स पर भी चर्चा कर रहे हैं।

फ्यूल धन सस्ता होने की उम्मीद क्यों?

पिछली तीन तिमाहियों में मजबूत मुनाफे के कारण ओएमसी का कुल घाटा कम हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तीन ओएमसी आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल का ज्वॉइंट प्रॉफिट पिछली तिमाही में 28,000 हजार करोड़ रुपये था। चूंकि ओएमसी की अंडर-रिकवरी खत्म हो गई है, इसलिए सरकार सोच रही है कि कंज्यूमर्स को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में, मांग में गिरावट और ओपेक+ सप्लाई कटौती को बढ़ाने को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है।

इससे पहले मिंट ने एनालिस्टों के हवाले से खबर दी थी कि तेल की गिरती कीमतों से भारत को महंगाई कम करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया था कि तेल की कीमतों में गिरावट से भारतीय इक्विटी बाजार को बढ़ावा मिलेगा, खासकर उन क्षेत्रों को जो कच्चे माल के रूप में कच्चे तेल का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत, तेल की कीमतों में गिरावट के कारण कुछ क्षेत्रों में गिरावट आ सकती है।

कितनी हो गई कच्चे तेल की कीमतें

अगर बात कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो काफी दिनों से 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चल रही है। बीते एक महीने से खाड़ी देशों का तेल औसनत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चल रहा है। जबकि अमेरिकी तेल की कीमतें एक महीने से औसत कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बनी हुई हैं। खाड़ी देशों का तेल सोमवार को 75.99 डॉलर प्रति बैरल से नीचे है। जबकि अमेरिकी तेल की कीमत 71.34 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री नवंबर में चार प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग के दम पर नवंबर में घरेलू यात्री वाहन थोक बिक्री में सालाना आधार पर चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनियों से डीलरों को यात्री वाहनों की आपूर्ति नवंबर में बढ़कर 3,34,130 इकाई हो गई। यह नवंबर महीने का अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा है। पिछले साल इसी महीने में 3,22,268 इकाइयों की आपूर्ति की गई थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री पिछले महीने 31 प्रतिशत बढ़कर 16,23,399 इकाई हो गई, जो नवंबर 2022 में 12,36,282 इकाई थी। इसी तरह तिपहिया वाहनों की आपूर्ति भी पिछले महीने 31 प्रतिशत बढ़कर 59,738 इकाई हो गई, जो पिछले साल नवंबर में 45,664 इकाई थी।

वाहन बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा, ''नवंबर के पहले पखवाड़े में समाप्त त्योहारी सीजन में मोटर वाहन उद्योग के सभी खंडों में मजबूत वृद्धि देखी गई। उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि के समर्थन से मोटर वाहन उद्योग वर्ष 2023 को उच्च स्तर पर समाप्त करने के लिए आशावादी है और उम्मीद करता है कि यह प्रवृत्ति 2024 तक जारी रहेगी।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि यात्री वाहन खंड में नवंबर 2023 में सालाना आधार पर 3.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3.34 लाख इकाइयों की आपूर्ति की गई। यह अब तक की सबसे अधिक थोक बिक्री है। उन्होंने कहा कि नवंबर में तिपहिया वाहनों की आपूर्ति नवंबर 2017 के अभी तक के उच्चतम स्तर से मामूली रूप से कम रही। इसी तरह पिछले महीने दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री भी नवंबर 2018 के उच्चतम स्तर से मामूली कम थी।

लहसुन की कीमतें मचा रहीं हाहाकार, 400 रुपए किलो पहुंचा भाव

नई दिल्ली। प्याज के बाद लहसुन के भाव सातवें आसमान पर हैं। कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। लहसुन अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। रिटेल बाजार में लहसुन की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। जानकारों के मुताबिक, लहसुन की कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम की मार के चलते लहसुन की फसल खराब हुई है। इसका असर लहसुन के उत्पादन पर पड़ा है। इस खराब फसल की वजह से आपूर्ति में गिरावट आई है। महाराष्ट्र में अब मुंबई के थोक व्यापारी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लहसुन खरीद रहे हैं। इससे रसद लागत और बाकी स्थानीय शुल्क बढ़ गए हैं। इसका असर लहसुन की कीमतों पर पड़ा है। लहसुन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है।

लहसुन की कम आपूर्ति के कारण पिछले कुछ हफ्तों में इसकी कीमत करीब दोगुना तक बढ़ चुकी है।

किसी कंपनी के लिए ईवी नीति को हल्का न करे सरकार: फिक्की ईवी समिति

नई दिल्ली। उद्योग मंडल फिक्की की इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर गठित समिति की प्रमुख सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी ने कहा है कि सरकार को %मेक इन इंडिया% पहल के प्रावधानों को किसी के लिए हल्का नहीं करना चाहिए और एक सुसंगत नीति का पालन करना चाहिए। मोटवानी का यह बयान अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला के भारत में अपना कारखाना स्थापित करने के लिए की जा रही विशेष रियायतों की मांग के बीच आया है।

बैटरी चालित तिपहिया वाहन, स्कूटर एवं ई-साइकिल की बिक्री करने वाली कंपनी काइनेटिक ग्रीन की संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोटवानी ने ईवी खंड के विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी के विकास पर भी जोर दिया। मोटवानी ने कहा, मेरा मानना है कि सरकार ने मेक इन इंडिया के लिए जो नीतियां लागू की हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए क्योंकि अब लोगों ने ईवी के स्थानीय विनिर्माण में निवेश करना शुरू कर दिया है। अगर इसका सही तरह से पालन नहीं किया गया तो विनिर्माता चीन समेत अन्य देशों का रुख कर सकते हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए सरकार से नीतिगत समर्थन मिलना चाहिए, मोटवानी ने कहा, मुझे इस प्रस्ताव का ब्योरा नहीं मालूम है लेकिन मुझे लगता है कि यह बड़े निवेश का मामला है। फिर भी मुझे निजी तौर पर लगता है कि नीति को लेकर भ्रम नहीं होना चाहिए और यह सुसंगत होनी चाहिए।

मोटवानी ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप कहें कि मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है.. और फिर आप कहें कि अब शुल्क कम हो गए हैं। नीति दीर्घकालिक और सुसंगत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को निश्चित रूप से मेक इन इंडिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होने पर हम एक ऐसा देश बन जाएंगे जहां ईवी उपयोगकर्ता तो हैं लेकिन उनके उत्पादन के लिए सामग्री दूसरे देशों से आ रही है। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बनाए रखने के लिए ईवी खरीद के लिए दिया जा रहा प्रोत्साहन जारी रखने की जरूरत है। मोटवानी ने कहा कि उद्योग निकाय इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के प्रोत्साहन के लिए संचालित फेम इंडिया योजना के तीसरे संस्करण के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को शामिल करने पर भी जोर दे रहा है।

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में लोकसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक बिजली की मांग में 50.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

अप्रैल–नवंबर में देश की बिजली खपत करीब 9% बढ़ी

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में बिजली की खपत पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब नौ प्रतिशत बढ़कर 1,099.90 अरब यूनिट हो गई जो आर्थिक गतिविधियों में उछाल को दर्शाती है। अप्रैल-नवंबर 2022-23 में देश में बिजली की खपत 1,010.20 अरब यूनिट रही थी। इसके पहले 2021-22 की समान अवधि में यह आंकड़ा 916.52 अरब यूनिट था। वित्त वर्ष 2022-23 की समूची अवधि में बिजली की खपत 1,504.26 अरब यूनिट थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 1,374.02 अरब यूनिट थी।

बिजली की मांग नवंबर में 204.86 गीगावाट रही

उद्योग विशेषज्ञों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में बिजली की खपत में लगभग नौ प्रतिशत की वृद्धि अर्थव्यवस्था में उछाल को दर्शाती है। बिजली मंत्रालय का अनुमान था कि गर्मियों के दौरान देश की बिजली की अधिकतम मांग 229 गीगावाट तक पहुंच जाएगी लेकिन बेमौसम बारिश होने से अप्रैल-जुलाई में मांग अनुमानित स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी।

हालांकि बिजली की अधिकतम मांग जून में 224.1 गीगावाट के नए शिखर पर पहुंच गई थी लेकिन जुलाई में यह गिरकर 209.03 गीगावाट पर आ गई। अगस्त में अधिकतम मांग 238.82 गीगावाट तक पहुंच गई। इस साल सितंबर में यह 243.27 गीगावाट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था लेकिन अक्टूबर में अधिकतम मांग 222.16 गीगावाट और नवंबर में 204.86 गीगावाट रही।

औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से बिजली की खपत बढ़ी

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल गर्मियों के दौरान देश के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होने से मार्च, अप्रैल, मई और जून में बिजली की खपत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में उमस रहने और त्योहारी मांग की वजह से औद्योगिक गतिविधियां तेज होने से बिजली की खपत बढ़ी।

1 फरवरी को आने वाले बजट में नहीं होगी कोई बड़ी घोषणा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक फरवरी, 2024 को पेश किए जाने वाले बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले पेश होने वाला लेखानुदान होगा। यह सीतारमण का छठा बजट होगा। सीतारमण ने सीआईआई-वैश्विक आर्थिक नीति मंच को संबोधित करते हुए कहा कि अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों के बाद चुनी हुई नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश करेगी।

सीतारमण एक फरवरी, 2024 को लोकसभा में एक अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। उन्होंने कहा, ''...यह सच है कि एक फरवरी, 2024 को जो बजट घोषित किया जाएगा। यह सिर्फ लेखानुदान होगा। इसका कारण अप्रैल-मई में होने वाला आम चुनाव है। इसीलिए सरकार जो बजट पेश करेगी वह सिर्फ तबतक के लिए सरकारी खर्चों को पूरा करने को लेकर होगा जबतक कोई नई सरकार नहीं बन जाती।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह फरवरी में पेश होने वाले बजट में बड़ी-बड़ी घोषणाएं करेंगी, उन्होंने कहा, ''उस समय (लेखानुदान में) कोई बड़ी घोषणा नहीं होगी। अतः आपको नई सरकार के आने तथा जुलाई, 2024 में पेश होने वाले पूर्ण बजट तक इंतजार करना होगा।

अरुण जेटली के बीमार पड़ने के बाद वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने 2019 में अंतरिम बजट पेश किया था। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया गया था। उन्होंने पांच जुलाई, 2019 को पूर्ण बजट पेश किया था। वास्तव में लेखानुदान के जरिये नई सरकार के कार्यभार संभालने तक कुछ जरूरी खर्च करने के लिए व्यवस्था की जाती है।

8,000 से ज्यादा कारोबारियों को केंद्रीय जीएसटी ने भेजा नोटिस

रायपुर। टैक्स चोरी करने के साथ ही रिटर्न जमा नहीं करने वाले छत्तीसगढ़ के 8,000 से ज्यादा कारोबारियों को केंद्रीय जीएसटी ने नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि कारोबारियों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। विभाग के इस अभियान में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के मामले हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर इन कारोबारियों पर छापामार कार्रवाई भी जल्द की जा सकती है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी टैक्स चोर को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के मामलों को निपटाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया था।

कौन थी वह औरत

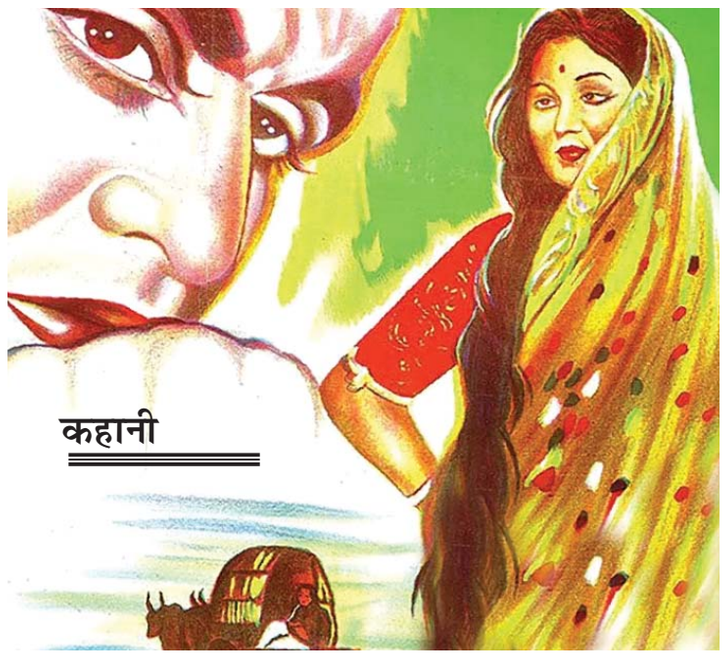

अपनी पत्नी सरला को अस्पताल के इमरजैंसी विभाग में भरती करवा कर मैं उसी के पास कुरसी पर बैठ गया. डाक्टर ने देखते ही कह दिया था कि इसे जहर दिया गया है और यह पुलिस केस है. मैं ने उन से प्रार्थना की कि आप इन का इलाज करें, पुलिस को मैं खुद बुलवाता हूं. मैं सेना का पूर्व कर्नल हूं. मैं ने उन को अपना आईकार्ड दिखाया, ''प्लीज, मेरी पत्नी को बचा लीजिए.'' डाक्टर ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर तुरंत इलाज शुरू कर दिया. मैं ने अपने क्लब के मित्र डीसीपी मोहित को सारी बात बता कर तुरंत पुलिस भेजने का आग्रह किया. उस ने डाक्टर से भी बात की. वे अपने कार्य में व्यस्त हो गए. मैं बाहर रखी कुरसी पर बैठ गया. थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पैक्टर और 2 कौंस्टेबल को आते देखा. उन में एक महिला कौंस्टेबल थी.

मैं भाग कर उन के पास गया, ''इंस्पैक्टर, मैं कर्नल चोपड़ा, मैं ने ही डीसीपी मोहित साहब से आप को भेजने के लिए कहा था.'' पुलिस इंस्पैक्टर थोड़ी देर मेरे पास रुके, फिर कहा, ''कर्नल साहब, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं डाक्टरों से बात कर के हाजिर होता हूं.''

मैं वहीं रुक गया. मैं ने दूर से देखा, डाक्टर कमरे से बाहर आ रहे थे. शायद उन्होंने अपना इलाज पूरा कर लिया था. इंस्पैक्टर ने डाक्टर से बात की और धीरेधीरे चल कर मेरे पास आ गए. मैं ने इंस्पैक्टर से पूछा, ''डाक्टर ने क्या कहा कैसी है मेरी पत्नी क्या वह खतरे से बाहर है, क्या मैं उस से मिल सकता हूं '' एकसाथ मैं ने कई प्रश्न दाग दिए.

''अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. डाक्टर अपना इलाज पूरा कर चुके हैं. उन की सांसें चल रही हैं. लेकिन बेहोश हैं. 72 घंटे औब्जर्वेशन में रहेंगी. होश में आने पर उन के बयान लिए जाएंगे. तब तक आप उन से नहीं मिल सकते. हमें यह भी पता चल जाएगा कि उन को कौन सा जहर दिया गया है,'' इंस्पैक्टर ने कहा और मुझे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, ''बताएं कि वास्तव में हुआ क्या था '' ''दोपहर 3 बजे हम लंच करते हैं. लंच करने से पहले मैं वाशरूम गया और हाथ धोए. सरला, मेरी पत्नी, लंच शुरू कर चुकी थी. मैं ने कुरसी खींची और लंच करने के लिए बैठ गया. अभी पहला कौर मेरे हाथ में ही था कि वह कुरसी से नीचे गिर गई. मुंह से झाग निकलने लगा. मैं समझ गया, उस के खाने में जहर है. मैं तुरंत उस को कार में बैठा कर अस्पताल ले आया.''

''दोपहर का खाना कौन बनाता है '' ''मेड खाना बनाती है घर की बड़ी बहू के निर्देशन में.''

''बड़ी बहू इस समय घर में मिलेगी '' ''नहीं, खाना बनवाने के बाद वह यह कह कर अपने मायके चली गई कि उस की मां बीमार है, उस को देखने जा रही है.''

''इस का मतलब है, वह खाना अभी भी टेबल पर पड़ा होगा '' ''जी, हां.''

''और कौन कौन है, घर में '' ''इस समय तो घर में कोई नहीं होगा. मेरे दोनों बेटों का औफिस ग्रेटर नोएडा में है. वे दोनों 11 बजे तक औफिस के लिए निकल जाते हैं. छोटी बहू गुड़गांव में काम करती है. वह सुबह ही घर से निकल जाती है और शाम को घर आती है. दोनों पोते सुबह ही स्कूल के लिए चले जाते हैं. अब तक आ गए होंगे. मैं गार्ड को कह आया था कि उन से कहना, दादू, दादी को ले कर अस्पताल गए हैं, वे पार्क में खेलते रहें.''

इंस्पैक्टर नेसाथ खड़े कौंस्टेबल से कहा, ''आप कर्नल साहब के साथ इन के फ्लैट में जाएं और टेबल पर पड़ा सारा खाना उठा कर ले आएं. किचन में पड़े खाने के सैंपल भी ले लें. पीने के पानी का सैंपल भी लेना न भूलना. ठहरो, मैं ने फोरैंसिक टीम को बुलाया है. वह अभी आती होगी. उन को साथ ले कर जाना. वे अपने हिसाब से सारे सैंपल ले लेंगे.''

''घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं '' इंस्पैक्टर ने मुझ से पूछा. ''जी, नहीं.''

''सेना के बड़े अधिकारी हो कर भी कैमरे न लगवा कर आप ने कितनी बड़ी भूल की है. यह तो आज की अहम जरूरत है. यह पता भी चल गया कि जहर दिया गया है तो इसे प्रूफ करना मुश्किल होगा. कैमरे होने से आसानी होती. खैर, जो होगा, देखा जाएगा.'' इतनी देर में फोरैंसिक टीम भी आ गई. उन को निर्देश दे कर इंस्पैक्टर ने मुझ से उन के साथ जाने के लिए कहा.

''आप ने अपने बेटों को बताया '' ''नहीं, मैं आप के साथ व्यस्त था.''

''आप मुझे अपना मोबाइल दे दें और नाम बता दें. मैं उन को सूचना दे दूंगा.'' इंस्पैक्टर ने मुझ से मोबाइल ले लिया. फोरैंसिक टीम को सारी कार्यवाही के लिए एक घंटा लगा. टीम के सदस्यों ने जहर की शीशी ढूंढ़ ली. चूहे मारने का जहर था. मैं जब पोतों को ले कर दोबारा अस्पताल पहुंचा तो मेरे दोनों बेटे आ चुके थे. एक महिला कौंस्टेबल, जो सरला के पास खड़ी थी, को छोड़ कर बाकी पुलिस टीम जा चुकी थी. मुझे देखते ही, दोनों बेटे मेरे पास आ गए.

''पापा, क्या हुआ '' ''मैं ने सारी घटना के बारे में बताया.''

''राजी कहां है '' बड़े बेटे ने पूछा. ''कह कर गई थी कि उस की मां बीमार है, उस को देखने जा रही है. तुम्हें तो बताया होगा ''

''नहीं, मुझे कहां बता कर जाती है.'' ''वह तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है. मैं तुम्हें समझाता रहा कि जमाना बदल गया है. एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल है. संयुक्त परिवार का सपना, एक सपना ही रह गया है. पर तुम ने मेरी एक बात न सुनी. तब भी जब तुम ने रोहित के साथ पार्टनरशिप की थी. तुम्हें 50-60 लाख रुपए का चूना लगा कर चला गया.

''तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सबकुछ पता था. मौल में चोरी करते रंगेहाथों पकड़ी गई थी. चोरी की हद यह थी कि हम कैंटीन से 2-3 महीने के लिए सामान लाते थे और यह पैक की पैक चायपत्ती, साबुन, टूथपेस्ट और जाने क्याक्या चोरी कर के अपने मायके दे आती थी और वे मांबाप कैसे भूखेनंगे होंगे जो बेटी के घर के सामान से घर चलाते थे. जब हम ने अपने कमरे में सामान रखना शुरू किया तो बात स्पष्ट होने में देर नहीं लगी. ''चोरी की हद यहां तक थी कि तुम्हारी जेबों से पैसे निकलने लगे. घर में आए कैश की गड्डियों से नोट गुम होने लगे. तुम ने कैश हमारे पास रखना शुरू किया. तब कहीं जा कर चोरी रुकी. यही नहीं, बच्चों के सारे नएनए कपड़े मायके दे आती. बच्चे जब कपड़ों के बारे में पूछते तो उस के पास कोई जवाब नहीं होता. तुम्हारे पास उस पर हाथ उठाने के अलावा कोई चारा नहीं होता.

''अब तो वह इतनी बेशर्म हो गई है कि मार का भी कोई असर नहीं होता. वह पागल हो गई है घर में सबकुछ होते हुए भी. मानता हूं, औरत को मारना बुरी बात है, गुनाह है पर तुम्हारी मजबूरी भी है. ऐसी स्थिति में किया भी क्या जा सकता है. ''तुम्हें तब भी समझ नहीं आई. दूसरी सोसाइटी की दीवारें फांदती हुई पकड़ी गई. उन के गार्डो ने तुम्हें बताया. 5 बार घर में पुलिस आई कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें सिखाती है और तुम उसे मारते हो. जबकि सारे उलटे काम वह करती है. हमें बच्चों के जूठे दूध की चाय पिलाती थी. बच्चों का बचा जूठा पानी पिलाती थी. झूठा पानी न हो तो गंदे टैंक का पानी पिला देती थी. हमारे पेट इतने खराब हो जाते थे कि हमें अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था. पिछली बार तो तुम्हारी मम्मी मरतेमरते बची थी.

''जब से हम अपना पानी खुद भरने लगे, तब से ठीक हैं.'' मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए रुका, ''तुम मारते हो और सभी दहेज मांगते हैं, इस के लिए वह मंत्रीजी के पास चली गई. पुलिस आयुक्त के पास चली गई. कहीं बात नहीं बनी तो वुमेन सैल में केस कर दिया. उस के लिए हम सब 3 महीने परेशान रहे, तुम अच्छी तरह जानते हो. तुम्हारी ससुराल के 10-10 लोग तुम्हें दबाने और मारने के लिए घर तक पहुंच गए. तुम हर जगह अपने रसूख से बच गए, वह बात अलग है. वरना उस ने तुम्हें और हमें जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी. इतना सब होने पर भी तुम उसे घर ले आए जबकि वह घर में रहने लायक लड़की नहीं थी.

''हम सब लिखित माफीनामे के बिना उसे घर लाना नहीं चाहते थे. उस के लिए मैं ने ही नहीं, बल्कि रिश्तेदारों ने भी ड्राफ्ट बना कर दिए पर तुम बिना किसी लिखतपढ़त के उसे घर ले आए. परिणाम क्या हुआ, तुम जानते हो. वुमेन सैल में तुम्हारे और उस के बीच क्या समझौता हुआ, हमें नहीं पता. तुम भी उस के साथ मिले हुए हो. तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने पास रखे हो. तुम महास्वार्थी हो. ''शायद बच्चों के कारण तुम्हारा उसे घर लाना तुम्हारी मजबूरी रही होगी या तुम मुकदमेबाजी नहीं चाहते होगे. पर, जिन बच्चों के लिए तुम उसे घर ले कर आए, उन का क्या हुआ पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी बेटी को होस्टल भेजना पड़ा और बेटे को भेजने के लिए तैयार हो. उस ने तुम्हें हर जगह धोखा दिया. तुम्हें किन परिस्थितियों में उस का 5वें महीने में गर्भपात करवाना पड़ा, तुम्हें पता है. उस ने तुम्हें बताया ही नहीं कि वह गर्भवती है. पूछा तो क्या बताया कि उसे पता ही नहीं चला. यह मानने वाली बात नहीं है कि कोई लड़की गर्भवती हो और उसे पता न हो.''

''जब हम ने तुम्हें दूसरे घर जाने के लिए डैडलाइन दे दी तो तुम ने खाना बनाने वाली रख दी. ऐसा करना भी तुम्हारी मजबूरी रही होगी. हमारा खाना बनाने के लिए मना कर दिया होगा. वह दोपहर का खाना कैसा गंदा और खराब बनाती थी, तुम जानते थे. मिनरल वाटर होते हुए भी, टैंक के पानी से खाना बनाती थी. ''मैं ने तुम्हारी मम्मी से आशंका व्यक्त की थी कि यह पागल हो गई है. यह कुछ भी कर सकती है. हमें जहर भी दे सकती है. किचन में कैमरे लगवाओ, नौकरानी और राजी पर नजर रखी जा सकेगी. तुम ने हामी भी भरी, परंतु ऐसा किया नहीं. और नतीजा तुम्हारे सामने है. वह तो शुक्र करो कि खाना तुम्हारी मम्मी ने पहले खाया और मैं उसे अस्पताल ले आया. अगर मैं भी खा लेता तो हम दोनों ही मर जाते. अस्पताल तक कोई नहीं पहुंच पाता.''

इतने में पुलिस इंस्पैक्टर आए और कहने लगे, ''आप सब को थाने चल कर बयान देने हैं. डीसीपी साहब इस के लिए वहीं बैठे हैं.'' थाने पहुंचे तो मेरे मित्र डीसीपी मोहित साहब बयान लेने के लिए बैठे थे. उन्होंने कहा, ''मुझे सब से पहले आप की छोटी बहू के बयान लेने हैं. पता करें, वह स्कूल से आ गई हो, तो तुरंत बुला लें.''

छोटी बहू आई तो उसे सीधे डीसीपी साहब के सामने पेश किया गया. उसे हम में से किसी से मिलने नहीं दिया गया. डीसीपी साहब ने उसे अपने सामने कुरसी पर बैठा, बयान लेने शुरू किए.

2 इंस्पैक्टर बातचीत रिकौर्ड करने के लिए तैयार खड़े थे. एक लिपिबद्ध करने के लिए और एक वीडियोग्राफी के लिए. डीसीपी साहब ने पूछना शुरू किया-

''आप का नाम '' ''जी, निवेदिका.''

''आप की शादी कब हुई कितने वर्षों से आप कर्नल चोपड़ा साहब की बहू हैं '' ''जी, मेरी शादी 2011 में हुई थी.

6 वर्ष हो गए.'' ''आप के कोई बच्चा ''

''जी, एक बेटा है जो मौडर्न स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता है.'' ''आप को अपनी सास और ससुर से कोई समस्या मेरे कहने का मतलब वे अच्छे या आम साससुर की तरह तंग करते हैं ''

''सर, मेरे साससुर जैसा कोई नहीं हो सकता. वे इतने जैंटल हैं कि उन का दुश्मन भी उन को बुरा नहीं कह सकता. मेरे पापा नहीं हैं. कर्नल साहब ने इतना प्यार दिया कि मैं पापा को भूल गई. वे दोनों अपने किसी भी बच्चे पर भार नहीं हैं. पैंशन उन की इतनी आती है कि अच्छेअच्छों की सैलरी नहीं है. दवा का खर्चा भी सरकार देती है. कैंटीन की सुविधा अलग से है.'' ''फिर समस्या कहां है ''

''सर, समस्या राजी के दिमाग में है, उस के विचारों में है. उस के गंदे संस्कारों में है जो उस की मां ने उसे विरासत में दिए. सर, मां की प्रयोगशाला में बेटी पलती और बड़ी होती है, संस्कार पाती है. अगर मां अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी. अगर मां खराब है तो मान लें, बेटी कभी अच्छी नहीं होगी. यही सत्य है. ''सर, सत्य यह भी है कि राजी महाचोर है. मेरे मायके से 5 किलो दान में आई मूंग की दाल भी चोरी कर के ले गई. मेरे घर से आया शगुन का लिफाफा भी चोरी कर लिया, उस की बेटी ने ऐसा करते खुद देखा. थोड़ा सा गुस्सा आने पर जो अपनी बेटी का बस्ता और किताबें कमरे के बाहर फेंक सकती है, वह पागल नहीं तो और क्या है. उस की बेटी चाहे होस्टल चली गई परंतु यह बात वह कभी नहीं भूल पाई.''

''ठीक है, मुझे आप के ही बयान लेने थे. सास के बाद आप ही राजी की सब से बड़ी राइवल हैं.''

उसी समय एक कौंस्टेबल अंदर आया और कहा, ''सर, राजी अपने मायके में पकड़ी गई है और उस ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया है. उस की मां भी साथ है.'' ''उन को अंदर बुलाओ. कर्नल साहब, उन के बेटों को भी बुलाओ.''

थोड़ी देर बाद हम सब डीसीपी साहब के सामने थे. राजी और उस की मां भी थीं. राजी की मां ने कहा, ''सर, यह तो पागल है. उसी पागलपन के दौरे में इस ने अपनी सास को जहर दिया. ये रहे उस के पागलपन के कागज. हम शादी के बाद भी इस का इलाज करवाते रहे हैं.'' ''क्या यह बीमारी शादी से पहले की है ''

''जी हां, सर.'' ''क्या आप ने राजी की ससुराल वालों को इस के बारे में बताया था '' डीसीपी साहब ने पूछा.

''सर, बता देते तो इस की शादी नहीं होती. वह कुंआरी रह जाती.'' ''अच्छा था, कुंआरी रह जाती. एक अच्छाभला परिवार बरबाद तो न होता. आप ने अपनी पागल लड़की को थोप कर गुनाह किया है. इस की सख्त

से सख्त सजा मिलेगी. आप भी बराबर की गुनाहगार हैं. दोनों को इस की सजा मिलेगी.''

''डीसीपी साहब किसी पागल लड़की को इस प्रकार थोपने की क्रिया ही गुनाह है. कानून इन को सजा भी देगा. पर हमारे बेटे की जो जिंदगी बरबाद हुई उस का क्या हो सकता है, इस के पागलपन का प्रभाव हमारी अगली पीढ़ी पर भी पड़े. उस का कौन जिम्मेदार होगा हमारा खानदान बरबाद हो गया. सबकुछ खत्म हो गया.'' ''मानता हूं, कर्नल साहब, इस की पीड़ा आप को और आप के बेटे को जीवनभर सहनी पड़ेगी, लेकिन कोई कानून इस मामले में आप की मदद नहीं कर पाएगा.''

थाने से हम घर आ गए. सरला की तबीयत ठीक हो गई थी. वह अस्पताल से घर आ गई थी. महीनों वह इस हादसे को भूल नहीं पाई थी. कानून ने राजी और उस की मां को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई थी. जज ने अपने फैसले में लिखा था कि औरतों के प्रति गुनाह होते तो सुना था लेकिन जो इन्होंने किया उस के लिए 7 साल की सजा बहुत कम है. अगर उम्रकैद का प्रावधान होता तो वे उसे उम्रकैद की सजा देते.

ओशो- दर्शन

पिरामिड का रहस्य

एक फ्रेंच खोजी, इजिप्त के पिरामिडों में दस वर्षों तक खोज करता रहा है। उस आदमी का नाम है- बोविस। वह एक वैज्ञानिक और इंजीनियर है। वह यह देखकर बहुत हैरान हुआ कि कभी-कभी पिरामिड में कोई चूहा भूल से या बिल्ली घुस जाती है और फिर निकल नहीं पाती..भटक जाती और मर जाती है। पर पिरामिड के भीतर जब भी कोई चूहा या बिल्ली या कोई प्राणी मर जाता है तो सड़ता नहीं। सड़ता नहीं, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। वह ममीफाइड हो जाता है..सूख जाता है, सड़ता नहीं।

यह हैरानी की घटना है और बहुत अदभुत है। पिरामिड के भीतर इसके होने का कोई कारण नहीं है और ऐसे पिरामिड के भीतर जो कि समुद्र के किनारे हैं, जहां कि ह्युमिडिटी काफी है, जहां कि कोई भी चीज सड़नी ही चाहिये और जल्दी सड़ जानी चाहिये, उन पिरामिड के भीतर भी कोई मर जाए तो सड़ता नहीं। मांस ले जाकर रख दिया जाए तो सूख जाता है, दुर्गंध नहीं देता। मछली डाल दी जाए तो सूख जाती है, सड़ती नहीं। तो बहुत चकित हो गया। इसका तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। बहुत खोजबीन की। आखिर यह खयाल में आना शुरू हुआ कि शायद पिरामिड का जो शेप है, वही कुछ कर रहा है।

लेकिन शेप, आकार कुछ कर सकता है! सब खोज के बाद कोई उपाय नहीं था। दस साल की खोज के बाद बोविस को खयाल आया कि कहीं पिरामिड का जो शेप, जो आकृति है, वह तो कुछ नहीं करती! तो उसने एक छोटा पिरामिड माडल बनाया। छोटा सा, तीन-चार फीट का बेस लेकर, और उसमें एक मरी हुई बिल्ली रख दी। वह चकित हुआ, वह ममीफाइड हो गई, वह सड़ी नहीं। तब तो एक बहुत नये विज्ञान का जन्म हुआ और वह नया विज्ञान कहता है- ज्यामिट्री की जो आकृतियां हैं उनका जीवन ऊर्जाओं से बहुत संबंध है। और अब बोविस की सलाह पर यह कोशिश की जा रही है कि सारी दुनिया के अस्पताल पिरामिड की शक्ल में बनाये जाएं। उनमें मरीज जल्दी स्वस्थ होगा।

आपने सर्कस के जोकर को, हंसोड़े को जो टोपी लगाये देखा है, वह फूल्स कैप कहलाती है। उसी की वजह से कागज..जितने कागज से वह टोपी बनती है, वह फूल्स कैप कहलाता है। लेकिन बोविस का कहना है कि कभी दुनिया के बुद्धिमान आदमी वैसी टोपी लगाते थे। वह वाइज-कैप है, क्योंकि वह टोपी पिरामिड के आकार की है। और अभी बोविस ने प्रयोग किये हैं, फूल्स कैप के ऊपर। और उसका कहना है कि जिन लोगों को भी सिरदर्द होता है, वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं तत्क्षण उनका सिरदर्द दूर हो सकता है। जिनको भी मानसिक विकार हैं वे पिरामिड के आकार की टोपी लगाएं, उनके मानसिक विकार दूर हो सकते हैं। अनेक चिकित्सालयों में जहां मानसिक चिकित्सा की जाती है, बोविस की टोपी का प्रयोग किया जा रहा है और प्रमाणित हो रहा है कि वह ठीक कहता है।

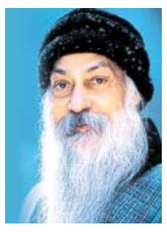

ओशो

विडम्बना

गांधी जी का कारागार

आगा खां पैलेस, यही वो जेल है जहाँ महात्मा मोहन दास करमचंद गांधी को 2 साल तक यातनाएं दी गई थीं। सजा इतनी कठोर थी कि बापू को स्नान करने के लिए 10-10 फि ट के संगमरमर लगे बाथरूम में नहाना पड़ता था।

सजा इतनी कठोर थी कि बापू को 8 गुणा 8 फि ट के नर्म, मुलायम मखमली बिस्तर में सोने के लिए मजबूर किया जाता था। सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें 20 एकड़ में फैले आगा खां पैलेस की हरी हरी मुलायम घास में घूमने के लिए मजबूर किया जाता था। सजा इतनी कठोर थी कि उन्हें 12 गुणा 12 फिट के स्टडी रूम में आलीशान टेबल कुर्सी में बेहतरीन इंग्लैंड के कागज में लेखन के लिए मजबूर किया गया।

और हां, सजा इतनी कठोर थी कि बापू की पत्नी भी साथ में रहती थी। सजा इतनी कठोर थी कि आने जाने के लिए मर्सडीज कार में बैठने को मजबूर किया जाता था।

और उधर वीर सावरकर को इतनी आसान सजा मिली थी ... हाथ पांव लोहे की जंजीरों से बंधे थे और दो जन्म की कालापानी की सजा थी जिसमें रोज कोल्हू से तेल निकालना पड़ता था। गांधी देश के बापू बन गए और सावरकर जी अंग्रेजो से माफी मानने वाले कहलाये।

जिसे विश्वास नही है वे पुणे में स्थित आगा खां पैलेस घूम आयें जो आज भी गांधी संग्रहालय के रूप में सुरक्षित है।

दस्तरख्वान

बिरयानी, समोसा और मुस्लिम खानसामा

बिरयानी शुद्ध ईरानी डिश है। बिरयानी शब्द भी फ ारसी भाषा का शब्द है। बिरयानी तुर्क व मुग़ल भारत लाए। बिरयानी भारत में मुस्लिम खानसामों व बावर्चियों के हाथ लगी तो उन्होंने इस के अंदर इतने तजुर्बे किए कि उस का टेस्ट बदल गया। आज ईरानियों को भी अच्छी बिरयानी खानी होती है, तो किसी इंडियन या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का रुख़ करता है।

समोसा भी ईरान से भारत आया। समोसे को फ ारसी में संबोसक कहते हैं जिस का अर्थ तीन कोने वाली चीज होता है। यही वजह है कि आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ इलाकों में समोसे को तिकोना कहा जाता है। ईरान और खाड़ी देशों में समोसे कई तरह के बनते हैं। आलू वाले समोसे, कीमे वाले समोसे, चिकन, पनीर या सब्जी भर कर भी समोसे बनाए जाते हैं। पूरे अरब वर्ल्ड में समोसे अफ्तारी के दस्तरख्वान का खास अंग हैं।

बिरयानी, समोसे, रसगुल्ले, जलेबी, हलीम, हरीस, गाजर का हलवा और शामी कबाब में खास बात यह है कि यह सब भारतीय डिश नहीं हैं। इसके बावजूद भारत के मुस्लिम खानसामों ने अपनी महारत से इसे असल से भी अच्छा और जायकेदार बना दिया है। कारीगरी के मामले में भारतीय मुसलमान खानसामों की मिसाल मिलना मुश्किल है।

आज ही से पीना शुरू करें पालक का जूस

शरीर के विकास के लिए हरे साग सब्जियों का सेवन बेहद जरूरी है. इसमें पालक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. इसमें कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और कई अन्य जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें मैगनीज, कैरोटीन, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, सोडियम, फौस्फोरस और आवश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं. इस खबर में हम आपको पालक जूस से होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे.

- पालक में एंटीऔक्सिडेंट पाए जाते हैं. इसके नियमित सेवन से त्वचा की झुर्रियां दूर रहती हैं और चेहरे पर चमक आती है.
- गर्भवती महिलाओं के लिए भी पालक का जूस पीने की सलाह दी जाती है. इससे गर्भ में पल रहे बच्चे को आयरन की कमी नहीं होती है.
- कई तरह के अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि पालक में मौजूद कैरोटीन और क्लोरोफिल कैंसर से बचने में हमारी मदद करता है. आंखों की रोशनी के लिए भी ये काफी असरदार होता है.
- इसमें विटामिन्स की अच्छी मात्रा होती है. इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है.
- पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए भी पालक के जूस के सेवन की राय दी जाती है. ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकाल कर पको स्वस्थ रखने का काम करती है. इसके अलावा कब्ज की परेशानी में भी खासा आराम देती है.
- अगर आपको त्वचा से संबंधित परेशानियां हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा. इसके नियमित सेवन से त्वचा पर चमक आती है. बालों के लिए भी ये काफी फायदेमंद है.

ठंड में जरूर खाएं विंटर सुपरफूड

सर्दियों में इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है। सर्दी-जुकाम और दूसरे इंफेक्शन शरीर को परेशान करते हैं। ऐसे में आपको शरीर को गर्म रखने वाले फूड अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। दरअसल, ठंड में सर्दी-जुकाम, बुखार-खांसी की शिकायत आपकी सेहत का मिजाज बिगाड़ सकती है। ठंड से बचने के लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही काफी नहीं हैं बल्कि डाइट में भी गर्म चीजों को शामिल करें। खाने-पीने को लेकर बरती गई लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। इसलिए आपको डाइट में इन 5 विंटर सुपरफूड को जरूर शामिल करना चाहिए। इनके सेवन से शरीर अंदर से गर्म रहेगा।

तिल- सर्दियों के सुपरफूड में तिल सबसे अहम हैं। ठंड में तिल का सेवन करने से शरीर में गर्मी आती है। तिल खाने से फाइबर, विटामिन.ई, कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं। इससे सर्दियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। तिल खाने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और शरीर अंदर से गर्म रहता है।

खजूर- विंटर सुपरफूड में खजूर को भी शामिल किया जाता है। रोजाना खजूर खाने से शरीर गर्म रहता है। खजूर के सेवन से शरीर को विटामिन-ए, विटामिन.बी, कैल्शियम, पोटैशियम और दूसरे कई विटामिन मिलते हैं। खजूर गर्म होता है इसके सेवन से शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है। खजूर सर्दियों में जरूर खाना चाहिए।

अंडे- ठंड में गर्मागरम अंडे खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं साथ ही शरीर को गर्म भी रखते हैं। रोजाना 1-2 अंडा जरूर खाएं। अंडे में प्रोटीन, विटामिन डी और विटामिन बी 12 पाया जाता है। सर्दियों में अंडा खाने से शरीर को गर्म रखने में मदद मिलती है।

गुड़- सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन, जिंक, कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है। गुड़ खाने से शरीर को एंटी ऑक्सीडेंट मिलते हैं जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। सर्दी-जुकाम से बचने के लिए गुड़ खा सकते हैं।

अदरक- ठंड में अदरक वाली चाय न सिर्फ पीने में स्वाद लगती है बल्कि ये सेहतमंद भी रखती है। अदरक में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। अदरक का सेवन करने से सर्दी जुकाम दूर रहता है।

सोशल मीडिया के चंगुल में राजनेता

वह दिन अब दूर नहीं जब इन्फ्लुएंसर को लोकसभा और विधानसभा की सीटें पकड़ाई जाएंगी. विधायिका में वैसे भी 33 प्रतिशत वीमेन रिजर्वेशन पास करवा दिया गया है. सोशल मीडिया पर वैसे भी रील बालाओं का जलवा है.पार्टियों के लिए अच्छी बात कि यहां अलगअलग जातियों और धर्मों की रील बालाएं हैं. यहां मैडम भी हैं तो नौकरानी भी. दोनों ही अपने अपने जोन में फेमस हैं. राजनीतिक पार्टियों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली.

सोशल मीडिया का नाम सुनते ही आजकल सब के दिमाग में बस एक ही नाम आता है इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम एक तरह से यह युवाओं का ऐसा अड्डा बन चुका है जहां युवा अपनी रिप्रेजैंटेशनल एक्सप्रैशन को जाहिर करता है,अपनी छोटी वीडियोज, जिन्हें रील्स कहा जाता है और अपनी पिक्चर शेयर करते हैं. बस, सवाल बनता है कि क्या वह इस तरह के प्लेटफौर्म्स को सही से यूज कर पा रहा है?

इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफौर्म है जहां पर यूजर्स न सिर्फ अपनी फोटो, वीडियो अपलोड करते हैं बल्कि नए दोस्त भी बनाते हैं और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए उन्हें किसी रिऐलिटी शो के आगे हाथ नहीं गिड़गिड़ाने होते. यही वजह है कि युवाओं ने इसे अपना अड्डा बना लिया है. इस में बहुत से युवा अपनी टैलेंट वीडियो अपलोड कर के दुनिया में नाम कमा रहे हैं.

कई लोग गाना, डांस, मेकअप, स्टाइलिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, स्टडी टिप्स और न्यूज जैसी रील्स बना कर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं. इन्हें देखने और फौलो करने वालों की संख्या भी हजारोंलाखों में है. यही फौलोअर्स उन की कमाई का जरिया भी हैं.

वहीं, कुछ लोग इस पर दिनरात अपना समय भी बरबाद कर रहे हैं, जिन का काम सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स देखना है. इस तरह से वे सिर्फ समय की बरबादी कर रहे हैं. इन्हें यह समझना चाहिए कि इंस्ट्राग्राम पर रील्स देखने से कैरियर नहीं बनेगा. कैरियर बनाने के लिए इन्हें पढ़ाई करनी होगी. इस के अलावा अपने टैलेंट पर काम करना होगा. ऐसे खलिहर लोग सिवा वक्त की बरबादी के, सोसाइटी में अपना कोई योगदान नहीं दे रहे.

कहते हैं, 'अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं.' ऐसे ही इंस्टाग्राम के फायदे के साथसाथ कुछ नुकसान भी हैं. असल में इंस्टाग्राम के यूजर्स आपस में अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं, जो कि गलत है. सब का घर, फैमिली और फाइनैंशियल स्टेटस अलगअलग होता है. लेकिन यूजर्स यह भूल जाते हैं.

अगर कोई अमीर यूजर यूएस, यूके की ट्रिप एंजौय कर रहा है और उस की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है तो दूसरा यूजर जो फाइनैंशियली इतना स्ट्रौंग नहीं है, वह अपनेआप को उस से कंपेयर करने लगता है. जबकि दोनों का फाइनैंशियल स्टेटस बहुत अलग है. ऐसे में जब वह ट्रिप पर जा नहीं पाता तो वह डिप्रैस्ड हो जाता है.

इंस्टाग्राम हमारी मैंटल हैल्थ के लिए सही नहीं है. इस विषय में एक रिसर्च की गई. यूनाइटेड किंगडम की रौयल सोसाइटी फौर पब्लिक हैल्थ द्वारा प्रकाशित स्टेटस औफ मांइड रिसर्च में

इंस्टाग्राम को मैंटल हैल्थ के लिए सब से खराब सोशल मीडिया नैटवर्क कहा गया. यह हाईलैवल की टैंशन, डिप्रैशन, बदमाशी, फोमो की भावना जागने वाला प्लेटफौर्म माना गया.

इंस्टाग्राम कितना घातक साबित हो सकता है, यह तो आप जान ही गए हैं, इसलिए आप में कोई टैलेंट है तो वह आप जरूर इंस्टाग्राम पर खुद को दिखाएं, लेकिन इस के भीतर इतना न घुस जाएं कि आप को समस्या होने लगे.

अब तो राजनीति के धुरंधर नेता भी रील और शौर्ट वीडियोज बना रहे हैं. नेताओं की चलते हुए स्लो मोशन क्लिप वायरल हो रही हैं. हों भी क्यों न, रील वीडियोज में स्लो मोशन का गजब का खेल जो है. नेता समझ गए हैं, उन के लंबे उबाऊ भाषण युवा नहीं सुनना चाहते. अब तो महामानवों के भाषण भी झूठे, नीरस और बोझिल लग रहे हैं. सोसाइटी, इकौनोमी के लिए क्या अच्छा है, किस पार्टी के क्या मुद्दे हैं, युवा इस में इंट्रैस्टेड नहीं हैं. उन्हें20-25 सैकेंड का मजा चाहिए. वह तो नेताओं की वीडियो भी शोर्ट क्लिप में देख रहे हैं, उसी से अपनी समझ बना रहे हैं. वे 20-25 सैकंड लायक ही बच गए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में इस से आगे का वे न तो सोच पा रहे हैं न किसी चीज का मजा ले पा रहे हैं.

राजनीति में चुनाव के समय जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन जनता तो रील्स में डूबी है. सुबह उठने के साथ रील, संडास जाते रील, दातून करते रील, खाना बनाते रील्स, खाना खाते रील, रील बनाते रील्स, काम करते रील, यहां तक कि सोने से पहले रील ही रील. अगर तर्जनी उंगली और अंगूठे की जांच की जाए तो हाथों की आधी रेखाएं मिटी दिखेंगी. अब जाहिर है युवा रील पर हैं तो नेता क्यों न हों? जहां जनता वहां नेता.

आजकल राजनीतिक पार्टियां पेड प्रमोशनल वीडियो बनवा रही हैं. उन के पीआर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को पकड़ रहे हैं. दोनों कोलेबोरेशन कर रहे हैं, पोडकास्ट हो रहे हैं, घंटे डेढ़ घंटे इंटरव्यू हो रहे हैं. लंबी इंटरव्यू वीडियोज में आधे से ज्यादा इज्जत खातिरदारी वाले सवाल किए जा रहे हैं, इमेज बिल्डिंग की जा रही है, हां,20-30 सैकंड का तड़कताभड़कता सवाल बीच में किया जा रहा है, जिसे शौर्ट बना कर सोशल मीडिया पर ठेला जा रहा है.

वह दिन अब दूर नहीं जब इन्फ्लुएंसर को लोकसभा और विधानसभा की सीटें पकड़ाई जाएंगी. विधायिका में वैसे भी 33 प्रतिशत वीमेन रिजर्वेशन पास करवा दिया गया है. सोशल मीडिया पर वैसे भी रील बालाओं का जलवा है.पार्टियों के लिए अच्छी बात कि यहां अलगअलग जातियों और धर्मों की रील बालाएं हैं. यहां मैडम भी हैं तो नौकरानी भी. दोनों ही अपनेअपने जोन में फेमस हैं. राजनीतिक पार्टियों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली. करना क्या है, बस फौलोअर्स ही तो देखने हैं, अपनी पार्टी हित देखते कैंडिडेट चुनने हैं. जो जितना पौपुलर, जिस के लचक में जितना दम, उस के उतने चांस.

कारण भी है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बिग बौस विजेता के लिए वोट मांगे जा रहे हैं और इन वीडियोज को देख कर खलिहर लाखों युवा में वोट डाल रहे हैं, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए सड़कों के ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, जैसे किसी बाहुबली नेता के लिए गुर्गे निकल पड़ते हैं, घर से पिता की जेब से चुराए पैसों से गाड़ियों में पैट्रोल भर कर सड़कों पर हुडदंग कर रहे हैं और टीवी पर आ कर पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं तो ऐसे ही इंस्टाग्राम पर रील्स देख कर ये अपने कैंडिडेट भी चुन ही लेंगे. लगता है भारत का भविष्य इन्हीं के भरोसे हो चला है.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक - नरेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आसमां पब्लिशर्स इंडिया प्रा.लि. जयराम काम्पलेक्स गली, मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं 6, विकास विहार कालोनी, सांई वाटिका,जोरातालाब के पास रायपुरा, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मो. 88171-94979